घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 227- गुरूवार 18- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिन में एफआईआर, रात में मौत का तांडव!

शाम 4:47 बजे दर्ज हुई मारपीट की रिपोर्ट,कुछ घंटे बाद जलती गाड़ी में मिली लाशें

नौगई की जलती रात...रेत के वर्चस्व की लड़ाई में तीन जिंदगियां राख...पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर गया कोरिया का हत्याकांड

दिन में मारपीट और एफआईआर, रात में आग और मौत का तांडव

वाहन में आग लगने से तीन की मौत, घायल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे

- नौगई हत्याकांड ने खड़े किए दर्जनों सवाल, रेत कारोबार की रंजिश में तीन की मौत,पूरा प्रदेश स्तब्ध
- रेत के वर्चस्व की लड़ाई या पूर्व नियोजित साजिश? पुलिस जांच के केंद्र में पूरा घटनाक्रम

नागेंद्र सिंह शिक्षक मृतक

भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह मृतक

मनोज त्रिपाठी भाजपा मेला घटना का आरोपी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले-गुनहगारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा...

कोरिया/सोनहत,17 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के नौगई गांव में मंगलवार की रात जो कुछ हुआ, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है, रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से चल रही तनातनी आखिरकार ऐसी खूनी परिणति तक पहुंच जाएगी,इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी,दिन में थाने में दर्ज हुई मारपीट की शिकायत और उसी रात तीन लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे घटनाक्रम को रहस्य,साजिश और कई अनुत्तरित सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है,घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे जिले में लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि विवाद सीधे मौत और आग की लपटों तक पहुंच गया।

तीन मौतें...दो जिंदगी की जंग लड़ रहे- पूरे परिवार पर टूटा कहर

नौगई की इस भयावह घटना में भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह,वीरेंद्र सिंह और शिक्षक नागेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत हो गई,वहीं मयंक सिंह और योगेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में उपचाराधीन हैं,घायलों की स्थिति को देखते हुए चिकित्सक लगातार निगरानी बनाए हुए हैं,जांच एजेंसियों की नजर भी विशेष रूप से घायलों के बयानों पर टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनके बयान इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

एफआईआर की टाइमिंग ने बढ़ाया रहस्य

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह एफआईआर है जो घटना वाले दिन ही थाना सोनहत में दर्ज हुई,दर्ज शिकायत में रास्ता रोकने,गाली-गलौज,मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर के अनुसार शिकायत शाम 4:47 बजे दर्ज की गई थी,यहीं से पूरे मामले में एक नया सवाल जन्म लेता है,यदि दिन में विवाद और तनाव की जानकारी पुलिस को थी,तो क्या रात में होने वाली संभावित हिंसा को रोका जा सकता था? क्या दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी?

कुछ घंटों बाद बदल गया पूरा मंजर

दिन में थाने तक सीमित दिख रहा विवाद रात होते-होते खूनी संघर्ष में बदल गया,आरोप है कि वाहन रोके गए, टक्कर मारी गई और उसके बाद वाहन में आग लग गई,इस आग में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा,सिहर उठा। जली हुई गाड़ियां,राख में तब्दील सामान और चारों तरफ पसरी खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि नौगई ने उस रात एक ऐसा मंजर देखा जिसे लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे।

पेट्रोल का सवाल जांच का सबसे बड़ा बिंदु

पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा उस पेट्रोल को लेकर हो रही है जिससे वाहन में आग लगाए जाने की बात कही जा रही है,यदि जांच में यह तथ्य सही साबित होता है,तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि पेट्रोल वहां संयोग से मौजूद था या पहले से तैयारी के तहत लाया गया था,कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी घटना में ज्वलनशील पदार्थ का पूर्व प्रबंध पाया जाता है तो यह जांच को सीधे पूर्व नियोजित साजिश की दिशा में ले जाता है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष केवल फोरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा।

मनोज त्रिपाठी समेत कई नामजद, फिर भी कई आरोपी रहे पुलिस की पकड़ से दूर-पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी,विशाल त्रिपाठी,अमन त्रिपाठी,अक्षय त्रिपाठी,सत्य कुमार त्रिपाठी, गौरव त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी और महेंद्र त्रिपाठी के नाम शामिल किए गए हैं,जबकि अन्य आरोपियों की पहचान 'अन्य' के रूप में दर्ज की गई है, घटना के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया,लेकिन लंबे समय तक कई नामजद आरोपियों के संबंध में पुलिस के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होने की चर्चा भी क्षेत्र में होती रही।

रेत का कारोबार और बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई- स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं था,क्षेत्र में रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर लंबे समय से प्रतिस्पर्धा और तनाव की स्थिति बनी हुई थी, करोड़ों रुपये के इस कारोबार में प्रभाव,क्षेत्र और नियंत्रण को लेकर कई बार विवाद सामने आते रहे हैं,नौगई की घटना ने पहली बार इस संघर्ष को इतनी भयावह तस्वीर के साथ प्रदेश के सामने ला खड़ा किया है,कहा जाता है कि लल्ला सिंह का पक्ष क्षेत्र में रेत कारोबार से जुड़ा हुआ था,जबकि मनोज त्रिपाठी परिवार भी ठेकेदारी व्यवसाय में सक्रिय था,रेत परिवहन और उपयोग को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से मतभेद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी, यह विवाद पहले थाने तक भी पहुंच चुका था, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा रहा है।

क्या दोनों पक्षों का रसूख बना लोगों की चुप्पी का कारण?

ग्रामीणों के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि इतनी बड़ी घटना के दौरान बचाव के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया, कुछ लोगों का मानना है कि दोनों पक्ष प्रभावशाली और रसूखदार थे, इसलिए लोग हस्तक्षेप करने से बचते रहे, वहीं कुछ का कहना है कि पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, यह पहलू भी जांच का हिस्सा बन सकता है कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने क्या देखा और क्या परिस्थितियां थीं।

घायल प्रत्यक्षदर्शी खोल सकते हैं पूरे राज

जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी उम्मीद अब उन घायलों से है जो घटना के समय मौके पर मौजूद थे,अस्पताल में उपचाराधीन लोगों के बयान पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल सकते हैं,पुलिस सूत्रों का मानना है कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान,कॉल डिटेल रिकॉर्ड,फोरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्य मिलकर यह तय करेंगे कि यह अचानक भड़की हिंसा थी या पहले से तैयार किया गया कोई खतरनाक प्लान।

राख के ढेर में तब्दील हो गया लल्ला सिंह का शव,घटना की नृशंसता से दहला इलाका

करीब 58 वर्षीय लल्ला सिंह की मौत के बाद सामने आई तस्वीरों ने पूरे कोरिया जिले को झकझोर दिया है,आग इतनी भीषण थी कि उनका शव लगभग राख में तब्दील हो गया और पहचान करना भी मुश्किल हो गया,घटना की क्रूरता और वीभत्सता ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है,स्थानीय लोग इसे जिले के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बता रहे हैं।

जेसीबी, हाईवा और टिपर से रास्ता रोकने की जनचर्चा,जांच के केंद्र में पूरी वारदात

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि घटना वाली रात लल्ला सिंह अपने साथियों के साथ लौट रहे थे,तभी रास्ते को जेसीबी, हाईवा और टिपर जैसे भारी वाहनों से अवरुद्ध किया गया,जनचर्चा के अनुसार वाहन रुकने के बाद विवाद बढ़ा और फिर हिंसक घटनाक्रम सामने आया, कुछ लोगों का दावा है कि वाहन को टक्कर मारकर आग लगाई गई, जबकि कुछ अन्य अलग घटनाक्रम बताते हैं। हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है,लेकिन पूरा घटनाक्रम अब पुलिस,फोरेंसिक टीम और जांच एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच बिंदु बन गया है।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जांच के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी,मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए?

आखिर कहां था प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग?

प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था अवैध खनन, फिर क्यों नहीं जागी व्यवस्था?

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भाजपा नेता एवं शिक्षक की जिंदा जलाकर हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली, अवैध खनन के नेटवर्क और कानून के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जिस प्रदेश में मानसून अवधि के दौरान रेत उत्खनन पर स्पष्ट प्रतिबंध लागू हो, वहां यदि रेत माफिया इतने शक्तिशाली हो जाएं कि विरोध करने वालों को जिंदा जलाने का दुस्साहस करें, तो सवाल केवल अपराधियों पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी उठेंगे।

कब जागेगी व्यवस्था?

सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है...

नौगई की उस रात की आग बुझ चुकी है,लेकिन सवाल अभी भी धधक रहे हैं, क्या दिन में दर्ज हुई एफआईआर और रात का हत्याकांड एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या वाहन में आग लगना अचानक हुई घटना थी या किसी पूर्व तैयारी का हिस्सा? क्या रेत कारोबार की प्रतिस्पर्धा ने तीन जिंदगियां निगल लीं? और सबसे महत्वपूर्ण— क्या अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे घायल इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और न्यायालयीन प्रक्रिया से सामने आएंगे,लेकिन फिलहाल नौगई की जलती रात ने पूरे छत्तीसगढ़ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कानून के डर से बड़ी कौन सी ताकत थी जिसने कुछ घंटों के भीतर विवाद को मौत के तांडव में बदल दिया।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल

मुंबई,17 जून 2026। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन टाइगर का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उनकी शिवसेना के 6 लोकसभा सांसद आखिरकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अब उद्धव गुट में केवल 3 लोकसभा सांसद बचे हैं। सभी बागी सांसद बुधवार को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने शिंदे से मुलाकात कर यह फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बागी सांसदों ने पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने शिवसेना में

शामिल होने की जानकारी दी। सांसदों ने बुधवार को शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे से भी मुलाकात की थी। अभी तक किसी भी सांसद ने सामने आकर बगावत की घोषणा नहीं की है।

पीएम मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बगैर जी-7 में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली,17 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का नाम लिए बगैर उनके हमले में मारे गए नाविकों का मुद्दा उठाया। मोदी ने आउटरीच सत्र में नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करना विषय पर बोलते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष से हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में कई भारतीय नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी। मोदी ने कहा, हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से हमारे मित्र देशों

को जान-माल का नुकसान हुआ। होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापार में आई बाधा से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। वैश्विक समुद्री व्यापार से सभी देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, और नाविक बिना भय के कार्य करें। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज ग्लोबल साउथ की विश्व समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा सहारे की नहीं, साथ की है। वे वैश्विक विकास के लाभार्थी नहीं,उसके भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा,हमें दाता-प्राप्तकर्ता की सोच से आगे बढ़कर,समान सहयोगी के रूप में काम करना होगा। उनके पास-पास नहीं, साथ-साथ चलना होगा। साझेदारी को निर्भरता के बजाय, गरिमा से जोड़ना होगा। इन प्रयासों से भावी पीढ़ियों के सतत-विकास की मजबूत नींव रख सकेंगे। मोदी का बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान युद्ध समाप्ति की ओर है और अमेरिका के साथ शांति समझौता होने जा रहा है। पिछले दिनों होर्मुज के पास ओमान के तट पर 3 तेल टैंकर जहाजों पर अमेरिका ने हमला किया था,जिसमें पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर सेट्टेबेलों पर हमले से 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। भारत ने अमेरिकी उच्चायोग के सामने यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, अमेरिका ने कोई अफसोस नहीं जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंपर्क सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर भाषण दिया। इससे पहले, पारंपरिक जी-7 समूह फोटो के बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

संपादकीय

महंगा होता इलाज

ऐसे वक्त में जब महंगाई के कारण जीवनयापन कठिन हो रहा है,नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एन.पी.पी.ए. द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की इजाजत देना कमजोर वर्गों के लिए 'कंगाली में आटा गीला होना' जैसा है। एन.पी.पी.ए. द्वारा जिन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दी गई है, उनमें कुछ कैंसर की दवाएं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के टीकों की कीमतों में पचास प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। निश्चय ही यह फैसला पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी विसंगतियों को दर्शाता है। निस्संदेह,भारत जैसे देश में जरूरी दवाओं को सस्ता रखना बेहद जरूरी है, जहां बहुत से परिवार इलाज का खर्च अपनी जेब से उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर,यह भी जरूरी है कि जीवनरक्षक दवाओं की बाजार में सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बहुत संभव है कि अमेरिका-ईरान युद्ध संकट से बाधित आपूर्ति श्रृंखला के चलते कुछ दवाइयों व टीकों की कीमतों में बढ़ोतरी को तार्किक बताया जाए, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में अमीर-गरीब की आर्थिक क्षमता को लेकर उठने वाले सवाल न्यायसंगत ही कहे जाएंगे। दरअसल,एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कमी और बढ़ती लागत को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। दलील दी गई कि यदि दवा बनाने वाली कंपनियां इनकी उत्पादन लागत नहीं निकाल पाती हैं तो वे खुले बाजार में इन दवाइयों की आपूर्ति बंद कर सकती हैं।

लेकिन इसके बावजूद गरीब तबके की सीमाओं और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल,इस बाबत दी गई दलीलों के बावजूद एक सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता कि इस देश में करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। निर्विवाद रूप से कैंसर के इलाज और बच्चों को बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों की कीमतों में पचास फीसदी बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गहरे आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। मरीजों के लिए इलाज के खर्च में दवाओं के अलावा,रोग की जांच,दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों तक की यात्रा,अस्पताल में भर्ती होने का खर्च तथा इस दौरान होने वाली आय की हानि भी शामिल होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ उन्हें इलाज और जीवित रहने के बीच कई मुश्किल फैसले लेने को मजबूर कर सकता है। इसका समाधान किफायती होने और उपलब्धता के बीच चयन करने में नहीं है,बल्कि एक ऐसा तंत्र विकसित करने में है,जो दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सरकार को सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने की जरूरत है। उसे सरकारी अस्पतालों के जरिये बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में जरूरी दवाइयों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे खास सब्सिडी के जरिये गरीब मरीजों को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया जा सके। इसके अलावा,दवाइयों की कीमतों से जुड़ी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए,जिससे पता चल सके कि वास्तव में दवाइयों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

विश्व शांति एवं संतुलन के लिए आत्ममंथन हो जी-7 बैठक में

जी-7 में अमेरिका,ब्रिटेन,फ्रांस,जर्मनी,इटली,कनाडा और जापान शामिल हैं,लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी दिशा और नीति निर्धारण पर अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ने सहयोग के बजाय दबाव और वर्चस्व की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों के साथ भी कई बार ऐसा व्यवहार किया है,मानो वे साझेदार नहीं बल्कि अमेरिकी नीतियों का अनुसरण करने वाले अनुयायी हों। टैरिफ युद्ध,व्यापारिक प्रतिबंध,रक्षा व्यय को लेकर दबाव और अनेक एकतरफा निर्णयों ने सदस्य देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। विशेषत: ईरान- इजरायल युद्ध ने समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था का धराशायी कर दिया और यह अब अमेरिका के कारण ही हुआ है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हिंसक संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की आशंका से भर दिया था। ईरान,इजरायल और इस क्षेत्र के अनेक गैर-राज्यीय समूह आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे थे।

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था,अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, जलवायु परिवर्तन,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,ऊर्जा सुरक्षा और युद्ध जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह मंच एकत्रित हुआ है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या जी-7 आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है,जितना उसकी स्थापना के समय था? क्या यह संगठन वास्तव में वैश्विक समस्याओं के समाधान का मंच बन पाया है अथवा यह कुछ शक्तिशाली देशों के हितों की रक्षा का माध्यम बनकर रह गया है? क्या इस मंच की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थों के चलते धुंधलाने में लगे हैं? विश्व में शांति स्थापना, संतुलित आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बने विभिन्न वैश्विक संगठनों की सफलता का मूल्यांकन उनके परिणामों से होता है, न कि उनके घोषणापत्रों से। दुर्भाग्य से जी-7 के संदर्भ में यह प्रश्न बार-बार उठता रहा है कि उसके निर्णयों और घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव कितना है। पिछले वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध,पश्चिम एशिया का संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता,जलवायु परिवर्तन की चुनौती और बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं के समाधान में यह संगठन अपेक्षित भूमिका निभाने में सफल नहीं दिखा है। यही कारण है कि जी-7 के भीतर आज पहले जैसी एकजुटता दिखाई नहीं देती। फ्रांस,जर्मनी,कनाडा और जापान जैसे देश कई मुद्दों पर अमेरिका से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर, वैश्विक व्यापार के नियमों पर और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह अपेक्षा करना कठिन है कि यह संगठन विश्व की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए कोई सर्वमान्य और प्रभावी रणनीति प्रस्तुत कर पाएगा। इस सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। भारत भले ही जी-7 का सदस्य न हो,लेकिन उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति,वैश्विक प्रतिष्ठा और विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्वरूप ने उसे इस मंच का एक महत्वपूर्ण सहभागी बना दिया है। यह अवसर केवल भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि उन विकासशील और निर्धन देशों की आकांक्षाओं को मुखर करने का भी है,जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में दब जाती है।

आज अफ्रीका,एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देश आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा,जलवायु आपदाओं और ऋण के बोझ से जूझ रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं जी-7 देशों की प्राथमिकताओं से भिन्न हैं। इसलिए भारत को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या विश्व की दिशा तय करने का अधिकार केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित रहना चाहिए? क्या वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक,समावेशी और प्रतिनिधिक नहीं बनाया जाना चाहिए? यह समय विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की चिंताओं को केंद्र में लाने का है। जी-7 की प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न उसकी प्रभावशीलता को लेकर है। यदि कोई संगठन विश्व की प्रमुख समस्याओं को रोकने या सुलझाने में सक्षम नहीं है, तो उसकी उपयोगिता स्वतः प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षों से जारी है। पश्चिम एशिया लगातार अशांत बना हुआ है। आतंकवाद और कट्टरता की चुनौतियां बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। इसके बावजूद वैश्विक नेतृत्व देने का दावा करने वाले मंचों की उपलब्धियां सीमित दिखाई देती हैं।

हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा शांति और सहमति की दिशा में बढ़ने की खबरों ने पूरी दुनिया को राहत दी है। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही थी और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। जैसे ही दोनों देशों के बीच समझौते और संवाद की संभावनाएं मजबूत हुईं,दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। निवेशकों का विश्वास बढ़ा, ऊर्जा बाजार में स्थिरता के संकेत मिले और तेल की कीमतों में नरमी आई। इससे स्पष्ट है कि शांति केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती,बल्कि उसका सीधा संबंध वैश्विक आर्थिक स्थिरता और आम नागरिक के जीवन से भी होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि संवाद और समझौता ही अंततः समाधान का मार्ग था,तो फिर टकराव और तनाव की स्थिति को इतना लंबा क्यों खींचा गया? आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को समझौते और सहमति के लिए राजी होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या इसके पीछे आर्थिक दबाव थे? क्या वैश्विक बाजारों की चिंता थी? क्या अमेरिकी जनता की अपेक्षाएं थीं? या फिर यह स्वीकारोक्ति थी कि युद्ध और दबाव की राजनीति की भी सीमाएं होती हैं?

ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर जी-7 जैसे मंचों में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विश्व समुदाय केवल औपचारिक शांति समझौतों से संतुष्ट नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि शांति स्थायी,विश्वसनीय और न्यायपूर्ण हो। यदि समझौते केवल राजनीतिक छवि निर्माण,चुनावी लाभ या अस्थायी रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं,तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जी-7 को यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शांति प्रयास वास्तविक हों और उनका उद्देश्य मानवता के हितों की रक्षा करना हो। आज वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही। भारत, चीन,ब्राजील,दक्षिण अफ्रीका,इंडोनेशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति संतुलन को नया स्वरूप दे रही हैं। ऐसे समय में जी-7 को भी अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। यदि यह मंच केवल अमेरिकी नेतृत्व और पश्चिमी हितों का प्रतिनिधि बना रहेगा,तो इसकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता लगातार घटती जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि जी-7 स्वयं को अधिक समावेशी बनाए, विकासशील देशों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक स्थान दे,आर्थिक न्याय और जलवायु न्याय के प्रश्नों पर ठोस पहल करे तथा वैश्विक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि नेतृत्व और प्रभुत्व में अंतर होता है। नेतृत्व विश्वास अर्जित करता है,जबकि प्रभुत्व विरोध को जन्म देता है। फ्रांस में हो रहा यह सम्मेलन केवल आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं होना चाहिए,बल्कि यह आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। जी-7 को यह विचार करना होगा कि बदलती दुनिया में उसकी भूमिका क्या है और वह किस प्रकार अधिक उपयोगी, प्रभावी और विश्वसनीय बन सकता है। यदि यह संगठन अपने भीतर बढ़ते मतभेदों को दूर कर,समानता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ता है, तभी वह विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेगा। भारत को इस अवसर पर साहसपूर्वक यह संदेश देना चाहिए कि विश्व का भविष्य शक्ति-संतुलन,संवाद, सहयोग और समावेशिता में निहित है। किसी एक देश या समूह की प्रभुत्ववादी सोच से नहीं,बल्कि साझी जिम्मेदारी और साझा विकास की भावना से ही विश्व में स्थायी शांति,आर्थिक स्थिरता और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही जी-7 जैसे मंचों की वास्तविक कसौटी भी।

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'
जांजगीर-चाम्पा
(छतीसगढ़)

रोटी और तिजोरी

लोहे-निर्मित उस जठर का अंतहीन विस्तार है
संचय की लोलुपता ही जिसका मूल आधार है
किन्तु मृत्तिका-निर्मित इस पेट की नियति अनुपम है
जो श्रम-कणों के स्वेद बिना केवल एक भ्रम है
एक ओर स्वर्ण की झंकार
अट्टालिकाओं में मौन मुस्कुराती है
दूसरी ओर चूल्हे की विद्रोही आंच
शिशुओं को बुभुक्षा-गीत सुनाती है।
लौह-कपाटों में बंद है राष्ट्र का कृत्रिम विकास,
जो मात्र विनिमय के पत्रों में पाता है सुवास।
पर वास्तविक भारत तो
खेतों की धूसरित माटी में गलता है
जहाँ कृषकों का शोणित
धमनियों के स्थान पर हल में ढलता है।
तुम कितनी भी सुदृढ़ कर लो
निज प्राचीरें और अर्गला
लोहे का यह घमंड एक दिन, स्वतः ही जाएगा गला।
जन-सामन्य के सब्र का,जब अंत्य बांध टूटेगा,
तब इस संचय-पात्र (तिजोरी) का
मिथ्या अहंकार भी छूटेगा।
क्षुधा-शमन ही इस सृष्टि का
शाश्वत और परम सत्य है,
यह संचय तो पूंजीवाद का केवल एक रुग्ण कृत्य है।
जिस दिन जागृत होगा, यह शोषित और सर्वहारा,
उस दिन केवल श्रमिक का हक होगा फिर कांपेगी धरा।

श्री गुरु अरजन देव जी शहीदी दिवस पर विशेष....

मानवता और सेवा के लिए शहीद गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान

संजय गोस्वामी,
अणुशक्तिनगर,मुंबई -94

2026 में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस 18 जून को मनाया जा रहा है। यह हर साल सिख कैलेंडर के तीसरे महीने जेठ की चौथी तारीख को मनाया जाता है। इस दिन का सिख समुदाय के लिए बहुत महत्व है।अप्रैल 1563 में रामदास और माता भानी के घर जन्मे, गुरु अर्जुन देव जी 18 साल की उम्र में पांचवें सिख गुरु थे। रु अर्जुन देव जी का जन्म अप्रैल 1563 में भारत के गोइंदवाल में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास और माता भानी थीं। उनके नाना और परदादा गुरु अमरदास और गुरु रामदास थे। अपने पिता की मौत के बाद,वे 1581 में 18 साल की उम्र में दस सिख गुरुओं में से पांचवें गुरु बने।मुगलों द्वारा उनकी असमय मौत के बाद,उनके बेटे 1606 में छठे गुरु बने। उनके बेटे के उत्तराधिकार को लेकर बहुत विवाद हुआ। उनके सबसे छोटे बेटे अर्जन को उत्तराधिकारी चुनने से सिखों में कई विवाद और फूट पड़ गई। पृथी चंद ने गुरु अर्जन का कड़ा विरोध किया और एक गुट बना लिया। गुरु अर्जन के अनुयायियों ने मीनास बनाया - जो अलग हुए गुट के साथ एक गठबंधन था। उन्हें 1604 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब बनाने की उनकी पहल के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक गुरुद्वारे में चार दरवाज़े भी डिज़ाइन किए और कहा कि उनका विश्वास सभी जातियों के लोगों के लिए है। अगस्त 1604 में,उन्होंने 'गुरु ग्रंथ साहिब' को इकट्ठा किया,जिसमें सभी पिछले गुरुओं की लिखी बातें एक किताब में हैं। उन्होंने गुरु राम दास के शुरू किए गए मसंद सिस्टम को फॉलो किया,जिसमें कहा गया था कि सिख अपनी इनकम का कम से कम दसवां हिस्सा सिख ऑर्गनाइज़ेशन 'दसवंद' को दान करें, जो गुरुद्वारों और लंगर बनाने के लिए पैसे देता था। 1606 में,उन्हें लाहौर किले में कैद कर लिया गया और मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें टॉर्चर किया और मार डाला,जिन्होंने उन पर जुर्माना लगाया था और कुछ भजन मिटा दिए थे जो उन्हें गलत लगे थे। उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेंपल बनवाने और 'गुरु ग्रंथ साहिब' को इकट्ठा करने की पहल की – यह एक ऐसी किताब थी जिसमें पिछले सभी गुरुओं की लिखी बातें थीं। उन्हें अपने समुदाय के लिए उनके कई योगदानों के लिए जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव जी सिख समुदाय के पहले शहीद हैं। इस दिन को लोग अलग-अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके और गुरुद्वारे में मुफ्त भोजन देकर याद करते हैं। इस दिन,सिख समुदाय गुरु अर्जुन देव जी की याद और शिक्षाओं का बहुत सम्मान करता है।श्री गुरु अर्जन देव जी,सिख धर्म के पांचवें गुरु थे और उन्हें 'शहीदों के सरताज' के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर 1606 में उन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया?उनका जीवन और योगदानआदि ग्रंथ का संकलनः 1604 में, उन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ,आदि ग्रंथ (जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना) का संकलन पूरा किया? हरिमंदिर साहिब की स्थापनाःउन्होंने अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की नींव रखी? मानवता के संदेशः उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और शांति का संदेश दिया? शहादत का कारण और घटनामुगल शासक जहांगीर उनके बढ़ते प्रभाव और उनकी शिक्षाओं से भयभीत था,जिस कारण उसने गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया? उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने और गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ शब्द हटाने का दबाव बनाया गया,जिसे गुरु जी ने सिरे से नकार दिया।इसके बाद उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं। उन्हें भीषण गर्मी में तपते लोहे के तवे पर बैठाया गया और उनके शरीर पर जलती हुई रेत डाली गई, फिर भी वे अडिग रहे और ईश्वर का सिमरन करते रहे 30 मई 1606 को इन अमानवीय यातनाओं को सहते हुए उन्होंने रावी नदी के तट पर अपना बलिदान दे दिया? गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया। वह एक बेहतरीन कलाकार और समानता के पक्के समर्थक थे। 1606 में,उन्हें मुगल राजा जहांगीर में, उन्हें लाहौर किले में कैद कर लिया गया, जहाँगीर ने उन्हें टॉर्चर किया और मार डाला।, जिससे वे सिख समुदाय के पहले शहीद बन गए।शहीदी दिवस का महत्वसिख इतिहास में वे पहले शहीद गुरु हैं? उनकी याद में हर साल सिख पंचांग के अनुसार शहीदी दिवस (मुख्य रूप से मई या जून के महीने में) बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है?

1606 में गुरु अर्जुन देव जी की शहादत एक अहम घटना थी,जिसने जुल्म के खिलाफ़ धार्मिक आज़ादी के लिए अटूट विश्वास और आखिरी कुर्बानी को दिखाया। उनकी मौत ने न्याय के प्रति सिखों के कमिटमेंट को और मज़बूत किया। गुरु अर्जुन देव जी की स्मृति में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर गुरुओं और मानवता के प्रति उनके योगदान के बारे आध्यात्मिक अनुभव होता है ,स्वर्ण मंदिर की भव्यता का दर्शन किया जाता है। आध्यात्मिक अनुभव के लिए मंदिर के चारों ओर फैले पवित्र जल में स्नान किया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी के दान और लंगर स्थापित करने के उपदेशों का पालन किया जाता है।

मोनिका डागा

बाबा

धीरे-धीरे अनुभव से सिखलाए जीने का तौर तरीका,
नन्हें सपनों में रंग भरने को दे पिता हाथों में तूलिका,
बेटा जहाँ राज दुलारा और बिटिया कहलाती मल्लिका,
थोड़ा डर ज्यादा अपनापन बाबा बिन लगता घर फीका।

अपनों की हँसी-खुशी के ही खातिर पिता पसीना बहाएं,
बाहर से सजाकर मुस्कान रोज ही भीतर चिंताएं दबाएं,
घर की जिम्मेदारियों को कंधों पर उम्र भर पिता उठाएं,
बच्चों की फरमाइशों में खुद के ख्वाब जो भूल जाएं।

हमें खुद से बेहतर बनाने को दिन रात करे जो परिश्रम,
अनबन हमारी सहकर भी नहीं कभी करें जो प्यार कम,
कभी सख्त रवैया भी अपनाएं पर ऑंखे रहे सदा नम,
दुनिया से कदम से कदम मिला चलना सिखाएं हरदम।

ऊँगली थाम कर बाबा की हर मुश्किल छोटी हो जाती,
बस बाबा के एक संग होने से हिम्मत दुगनी हो जाती,
अंधेरों में भी छोटी सी दुनिया चमचम रोशन हो जाती,
सिर पर हाथ रख देने भर से किस्मत जगमग हो जाती।

सीने में कितना दर्द छिपा क्या तुम्हें कुछ भी हैं मालूम,
पिता की रोक-टोक से मत हो जाना जरा भी गुमसुम,
छोटी-मोटी डांट डपट को सीने से चिपकाना मत तुम,
पिता का दाहिना हाथ बन मानना दिल से हर हुकुम।

दौड़ते हुए जूते, ठहरती हुई सांसें

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

कमरे का तापमान ठीक सोलह डिग्री पर लॉक था। इस कमरे में न धूप आती थी,न हवा,बस एक सफेद सी रोशनी थी जो चौबीसों घंटे जागती रहती थी ताकि मौत को आने में कोई गलतफहमी न हो। बेड नंबर चार पर लेटे सत्तर साल के दीनानाथ जी के मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क पर हर तीन सेकेंड बाद भाप जमती और पिघल जाती। यही उनके जिंदा होने का इकलौता सबूत था,जिसे देखकर बगल की कुर्सी पर बैठी नर्स सिस्टर मैरी अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थीं। रात के ठीक दो बज रहे थे। यह वह वक्त होता है जब अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि ग्लूकोज की टपकती बूंदों की आवाज भी किसी टाइम बम के टिक-टिक जैसी सुनाई देती है। सिस्टर मैरी ने अपनी घड़ी देखी। वह जानती थीं कि दीनानाथ जी के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। डॉक्टर आनंद ने शाम को ही राउंड पर कह दिया था कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है,बस सुबह का सूरज देखना मुश्किल है। अचानक दीनानाथ जी की उंगलियों में थोड़ी हरकत हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना मास्क एक तरफ सरकाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी,'मैरी...वो...वो आ गया क्या? 'मैरी ने उनके ठंडे पड़ रहे हाथ को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा,'कौन दीनानाथ जी? यमराज? अरे,अभी उनका सर्वर डाउन है,इतनी जल्दी नहीं आते वो।' मैरी का यह व्यंग्य दीनानाथ के चेहरे पर एक सूखी सी हंसी छोड़ गया। इस हॉस्पिस केयर यानी मरणासन्न मरीजों के आखिरी घर का यही नियम था यहाँ दर्द को दवाओं से ज्यादा चुटकुलों से सुखाया जाता था। दीनानाथ जी पिछले दो महीने से यहाँ थे। उनके फेफड़े जवाब दे चुके थे,पर उनकी आँखें हर रोज दरवाजे पर टिकी रहती थीं। वह किसी का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो इस कमरे की सफेद दीवारों से भी ज्यादा पथरीला था।

'मैरी,मेरी वसीयत...सब ठीक है न? कोर्ट का वो आदमी सुबह आएगा?'दीनानाथ ने हांफते हुए पूछा।'हाँ बाबा,सब तैयार है। आपके वकीलों ने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया है। बस आप सुबह तक दिल थाम के बैठिए,'मैरी ने उनके माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उनके लहजे में एक कड़वा मजाक था,जो दीनानाथ की अमीरी पर नहीं,बल्कि उस लाचारी पर था जो करोड़ों रुपये होने के बाद भी एक-एक सांस के लिए भीख मांग रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। भारी बूटों की आवाज। मैरी चौंक गई। इतनी रात गए कौन आ सकता था? दरवाजा धीरे से खुला। एक लंबा,सूट-बूट पहने नौजवान अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर थकावट से ज्यादा एक अजीब सी जल्दबाजी थी। उसने सीधे दीनानाथ के बेड की तरफ रुख किया। दीनानाथ की आँखों में जैसे बुझते हुए दीये की आखिरी लौ चमक उठी। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, 'अविनाश...तुम आ गए बेटा! मुझे मालूम था,तुम अपनी नौकरी,अपना लंदन का सब काम छोड़कर अपने बूढ़े बाप के आखिरी वक्त में जरूर आओगे। ' अविनाश ने अपनी महंगी घड़ी पर वक्त देखा और बिना कोई जज्बात दिखाए सीधे मैरी से मुखातिब हुआ, 'सिस्टर,डॉक्टर कहाँ हैं? ये कुछ जरूरी कागजात हैं, जिन पर इनके दस्तखत चाहिए। सुबह की मेरी लंदन की फ्लाइट है, बोर्ड मीटिंग मिस नहीं कर सकता। क्या ये होश में हैं?' कमरे का सन्नाटा जैसे और नुकीला हो गया। सिस्टर मैरी ने अविनाश को ऊपर से नीचे तक देखा। उस महंगे सूट की चमक के पीछे छुपा हुआ जो गिद्ध था,वह मैरी को साफ दिख रहा था। चिकित्सा विज्ञान ने भले ही इंसान को अमर बनाने की दवा न खोजी हो,पर ऐसे रिश्तों को जिंदा रखने का वेंटिलेटर जरूर ढूंढ लिया था। मैरी ने एक गहरी सांस ली और कहा,'हाँ सर,आपके पिता बिल्कुल होश में हैं। वो पिछले दो महीने से सिर्फ आपकी इस बोर्ड मीटिंग के लिए ही अपनी आखिरी सांसें रोककर बैठे थे। मेडिकल साइंस भी हैरान है कि जो इंसान बिना ऑक्सीजन के दो मिनट नहीं रह सकता,वो बेटे के मोह में दो महीने कैसे जी गया। 'अविनाश को इस व्यंग्य की चुभन महसूस तो हुई, पर उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं थी जो वो सीधा खड़ा हो पाता। उसने तुरंत अपने बैग से लीगल पेपर्स निकाले और दीनानाथ के सामने रख दिए,'डैड,प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। इसके बाद आपको इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर्स वैसे भी कह रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है। 'दीनानाथ ने कांपते हाथों से पेन थामा। उनकी आँखों से बहता हुआ पानी उस वसीयत के सफेद कागज पर गिरा और स्याही थोड़ी सी फैल गई। उन्होंने बिना पढ़े,अपने जीवन की आखिरी ऊर्जा समेटकर उस कागज पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत पूरे हुए, अविनाश ने झपट्टा मारकर वो कागज अपनी फाइल में सुरक्षित किए और एक राहत की सांस ली। 'थैंक यू डैड। अब मैं चलता हूँ। एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ। सिस्टर,इनका ख्याल रखिएगा,'अविनाश ने बिना मुड़े दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे अपने बाप के ठंडे होते शरीर को छूने तक का परहेज था,शायद मौत की छूत उसकी करोड़ों की डील को न लग जाए।

'अविनाश...'दीनानाथ की एक दबी हुई चीख कमरे में गूंजी। लेकिन अविनाश तब तक कॉरिडोर पार कर चुका था। उसकी परछाईं भी गायब हो चुकी थी। कमरे में फिर वही 'टिक-टिक'की आवाज लौट आई। दीनानाथ की आँखें अब छत को ताक रही थीं। मॉनिटर पर चलती हुई हरी लकीरें अब धीरे-धीरे सीधी होने की तरफ बढ़ रही थीं। बीप की आवाज की रफ्तार कम हो रही थी। सिस्टर मैरी ने चुपचाप उनके पास आकर बेडसाइड टेबल पर रखा एक लिफाफा उठाया। यह वह लिफाफा था जो दीनानाथ ने एक हफ्ते पहले मैरी को इस शर्त पर दिया था कि जब अविनाश आएगा,तब इसे खोला जाए।'दीनानाथ जी,आपका बेटा तो चला गया। क्या मैं अब इसे खोलूं?'मैरी की आवाज में एक भारीपन था।

सुविचार

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

सप्लायर तक पहुंची आबकारी टीम...लेकिन गढ़वा बॉर्डर पर क्यों थम जाती है जांच?

50 से ज्यादा प्रकरण,सैकड़ों इंजेक्शन जब्त,फिर भी नहीं टूट रहा नशे का नेटवर्क,खुद आबकारी अधिकारी ने गिनाईं संसाधनों की मजबूरियां

सरगुजा में नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। पहले वाहिद अंसारी,फिर उसके कथित सप्लायर मोशीम अंसारी की गिरफ्तारी...विभाग इसे बड़ी सफलता बता रहा है,लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है,वह किसी आरोपी पर नहीं बल्कि खुद विभाग की कार्यप्रणाली पर है। क्योंकि इस बार सवाल विपक्ष या आम लोगों ने नहीं उठाया,बल्कि विभाग के ही जिम्मेदार अधिकारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता के बयान ने कई परतें खोल दी हैं। रंजीत गुप्ता ने साफ कहा कि मोशीम अंसारी को नशीले इंजेक्शन गढ़वा के सप्लायरों से मिलते थे,लेकिन वहां तक पहुंचना आबकारी विभाग के लिए आसान नहीं है। संसाधन नहीं हैं,साइबर सेल नहीं है,हथियार नहीं हैं,फंड नहीं है।

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक तरफ आबकारी विभाग ने 24 घंटे के भीतर कैरियर से सप्लायर तक पहुंचकर अपनी सक्रियता दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसके कथित सप्लायर मोशीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 600 नशीले इंजेक्शनों की बरामदगी और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई को विभाग बड़ी सफलता मान रहा है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता द्वारा संसाधनों की कमी, सीमित अधिकार क्षेत्र और अन्य एजेंसियों के अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई की वास्तविक तस्वीर भी उजागर कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि विभाग को पहले से पता है कि नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई का स्रोत गढ़वा जैसे बाहरी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो आखिर वर्षों से कार्रवाई सप्लायर और स्थानीय नेटवर्क तक ही क्यों सिमटी हुई है?

24 घंटे में कार्रवाई,लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती

14 जून की रात सरना मैदान से वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ में उसने मोशीम अंसारी का नाम लिया और अगले ही दिन आबकारी टीम ने मोशीम अंसारी की दुकान से 400 और इंजेक्शन बरामद कर लिए। कार्रवाई तेज थी,परिणाम भी सामने आया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने यह भी साबित कर दिया कि स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। उनके पीछे कोई न कोई सप्लाई चैन सक्रिय है। यहीं से सवाल उठता है कि यदि मोशीम अंसारी तक पहुंचना संभव था तो उसके ऊपर की कड़ी तक पहुंचने में वर्षों से बाधा क्या है?

खुद अधिकारी ने बताई विभाग की बेबसी

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता का वह कथन है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मोशीम अंसारी को नशीले इंजेक्शन गढ़वा क्षेत्र के सप्लायरों से मिलते थे और वहां कार्रवाई करना आबकारी विभाग के लिए आसान नहीं है।, उनका कहना है कि आबकारी विभाग के पास न पर्याप्त बल है,न हथियार,न साइबर सेल और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधन। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में एक बार अंबिकापुर साइबर टीम की मदद से गढ़वा जाकर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1500 नशीले इंजेक्शन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था,लेकिन हर बार ऐसी मदद मिलना संभव नहीं होता। रंजीत गुप्ता का यह बयान एक अधिकारी की ईमानदार स्वीकारोक्ति माना जा सकता है, लेकिन साथ ही यह कई संस्थागत प्रश्न भी खड़े करता है। यदि विभाग खुद को सीमित संसाधनों वाला मानता है तो फिर लगातार सामने आ रहे अंतरराज्यीय नेटवर्क से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या आबकारी विभाग केवल अंतिम कड़ी पकड़ रहा है? पिछले एक वर्ष में संभागीय उड़नदस्ता टीम ने 50 से अधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। यह संख्या बताती है कि कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इतने प्रकरणों के बावजूद नशीले इंजेक्शनों की उपलब्धता खत्म नहीं हुई। हर कुछ सप्ताह में नई खेप पकड़ी जाती है। नए आरोपी सामने आते हैं। नई सप्लाई लाइन का खुलासा होता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या कार्रवाई मुख्यतः कैरियर,स्थानीय विक्रेता और छोटे सप्लायरों तक सीमित रह जाती है,जबकि बड़े नेटवर्क संचालक अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं?

घटती घटना | सरगुजा समाचार | अम्बिकापुर बुधवार 17 जून 2026 | 3

सुपरमैन रंजीत गुप्ता की वापसी! 24 घंटे में कैरियर से सप्लायर तक पहुंची आबकारी टीम,लेकिन क्या अब पूरे नशीले इंजेक्शन नेटवर्क का होगा खुलासा?

कल उठा था सवाल...आज मिली कार्रवाई की बड़ी मिसाल...वाहिद अंसारी के बयान पर मोशीम अंसारी गिरफ्तार,4 लाख के इंजेक्शन जब्त,फिर भी जांच की असली परीक्षा बाकी

50 से अधिक प्रकरण...फिर भी कारोबार जारी क्यों?

क्या इस विभाग भी आएगा मैदान में?

गढ़वा का नाम बार-बार क्यों आता है? नशीले इंजेक्शन के कई मामलों में जांच के दौरान झारखंड के गढ़वा क्षेत्र का नाम सामने आने की चर्चा होती रही है। यदि वास्तव में सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा वहां से संचालित हो रहा है तो फिर क्या दोनों राज्यों की एजेंसियों के बीच कोई स्थायी समन्वय तंत्र मौजूद है?

- क्या संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं?
- क्या अंतरराज्यीय नेटवर्क की आर्थिक जांच हो रही है?
- क्या कॉल डिटेल,बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की पड़ताल हो रही है?
- इन सवालों के जवाब अब तक सार्वजनिक नहीं हैं।

बैच नंबर की जांच से खुल सकता है बड़ा राज

विशेषज्ञों का मानना है कि जब्त इंजेक्शनों पर अंकित बैच नंबर पूरे नेटवर्क का सबसे मजबूत सुराग हो सकते हैं। यदि बैच नंबर के आधार पर यह पता लगाया जाए कि इंजेक्शन किस कंपनी ने बनाए,किस स्टॉकिस्ट को भेजे गए,किस एजेंसी ने खरीदे और किस मेडिकल प्रतिष्ठान तक पहुंचे,तो सप्लाई चेन की कई परतें सामने आ सकती हैं। लेकिन अब तक अधिकांश मामलों में जनता के सामने ऐसी जांच के परिणाम नहीं आए हैं। यही वजह है कि हर नई बरामदगी के बाद वही सवाल फिर खड़ा हो जाता है–आखिर माल आ कहां से रहा है?

इस विभाग की भूमिका पर भी सवाल

यह मामला केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी का नहीं है। यदि वैध दवा वितरण प्रणाली से नशीले इंजेक्शन अवैध बाजार तक पहुंच रहे हैं तो औषधि प्रशासन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

- क्या संबंधित मेडिकल दुकानों के रिकॉर्ड जांचे गए?
- क्या स्टॉक रजिस्टर का मिलान हुआ?
- क्या थोक विक्रेताओं से पूछताछ की गई?
- क्या लाइसेंसधारी एजेंसियों की जवाबदेही तय हुई?

यदि नहीं,तो जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी अधूरा माना जाएगा।

सुपरमैन की वापसी या सिस्टम की अधूरी जीत? दो लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल-क्या सप्लायर तक पहुंचेगी जांच?

सफलता भी...सिस्टम की कमजोरी भी...

सुपरमैन रंजीत गुप्ता और उनकी टीम ने वाहिद अंसारी से मोशीम अंसारी तक पहुंचकर यह जरूर दिखाया है कि कार्रवाई केवल दिखावे की नहीं थी। एक दिन पहले उठे सवाल का जवाब अगले दिन गिरफ्तारी के रूप में मिला। लेकिन इसी कार्रवाई ने यह भी उजागर कर दिया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल जज्बे के भरोसे नहीं जीती जा सकती। जब एक अधिकारी स्वयं कह रहा है कि विभाग के पास पर्याप्त संसाधन,तकनीकी सहायता,हथियार,साइबर समर्थन और अंतरराज्यीय कार्रवाई की क्षमता नहीं है,तब यह मामला केवल व्यक्तिगत कार्यक्षमता का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की क्षमता का बन जाता है।

सरगुजा पूछ रहा है...

- यदि गढ़वा से सप्लाई आने की जानकारी है तो वहां नियमित संयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती?
- 50 से अधिक प्रकरणों के बावजूद नेटवर्क खत्म क्यों नहीं हुआ?
- जब्त इंजेक्शनों के बैच नंबर की विस्तृत जांच हुई या नहीं?
- मेडिकल एजेंसियों और स्टॉकिस्टों की भूमिका की पड़ताल कहां तक पहुंची?
- क्या वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की जांच की जा रही है?
- क्या आबकारी विभाग को अंतरराज्यीय नेटवर्क से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं?
- क्या नशे के कारोबार के पीछे मौजूद बड़े संचालकों तक जांच पहुंचेगी?

क्या यही है निष्कर्ष..

मोशीम अंसारी की गिरफ्तारी ने यह साबित किया कि आबकारी विभाग स्थानीय सप्लायर तक पहुंच सकता है। लेकिन विभाग के अपने अधिकारी की स्वीकारोक्ति यह भी बताती है कि जांच अक्सर उस बिंदु पर पहुंचकर रुक जाती है,जहां से असली नेटवर्क शुरू होता है। सरगुजा में नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ लड़ाई की असली सफलता तब मानी जाएगी,जब केवल कैरियर और सप्लायर ही नहीं,बल्कि सप्लाई चेन के स्रोत,वित्तीय नेटवर्क,थोक कारोबारी और अंतरराज्यीय संचालक भी कानून के दायरे में आएं। फिलहाल कार्रवाई ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है,लेकिन जनता अब गिरफ्तारियों से ज्यादा उस सवाल का जवाब चाहती है–नशे का यह कारोबार आखिर संचालित कौन कर रहा है और उस तक कानून कब पहुंचेगा?

इनका है कहना...

सुपरमैन रंजीत गुप्ता के इस तर्क पर जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि झारखंड सीमा क्षेत्र से नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई की जानकारी लंबे समय से विभाग को है,तो वहां तक पहुंचने में लगातार असमर्थता के कारणों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि उक्त सीमा क्षेत्र से अधिकारी का व्यक्तिगत और पारिवारिक जुड़ाव होने की चर्चा स्थानीय स्तर पर होती रही है। उनके अनुसार इन तथ्यों और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों की निष्पक्ष जांच होने पर कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आ सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही इस संबंध में किसी सक्षम एजेंसी द्वारा कोई आधिकारिक निष्कर्ष जारी किया गया है। बावजूद इसके,उठ रहे सवालों ने पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग को और तेज कर दिया है।

बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को पड़ा भारी: बीच सड़क बेल्ट,डंडे और पत्थरों से बेरहमी से पीटा,5 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

मिशन अस्पताल के पास हुई वारदात का वीडियो चर्चा में...पुलिस ने कुछ दिनों बाद कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को दबोचा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। शहर में एक युवती से कथित छेड़छाड़ का विरोध करना उसके भाई को भारी पड़ गया। विरोध करने पर युवकों ने मिलकर उसकी बेल्ट,डंडे,पत्थरों और हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक एक युवक पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने शहर में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस के अनुसार घटना 10 जून की रात करीब 10:30 बजे की है। पीड़िता अपने भाई के साथ स्कूटी से गांधी चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान मिशन अस्पताल के पास कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि अतुल ताम्रकार ने युवती के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की और उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। जब युवती के भाई ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि अतुल ताम्रकार,रोहित केडिया और उनके अन्य साथियों ने मिलकर युवक को घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों, बेल्ट, बांस के डंडे तथा पत्थरों से हमला कर दिया। घटना के अगले दिन 11 जून को पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

वीडियो आने के बाद बढ़ी चर्चा : घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई। वीडियो में कुछ युवक एक युवक को घेरकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर हुई इस घटना ने लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ाई है।

डीआईजी-एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई : मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस की जांच में मामले में कुल सात आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिनमें पांच विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) और दो बालिग आरोपी शामिल हैं।

गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान: - अतुल ताम्रकार (21 वर्ष), निवासी केदारपुर, अंबिकापुर,रोहित केडिया (22 वर्ष), निवासी केदारपुर, अंबिकापुर बताई गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बेल्ट,डंडा,पत्थर और स्कूटी भी बरामद की है।

नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता चिंता का विषय : इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सात आरोपियों में पांच नाबालिग शामिल पाए गए। लगातार सामने आ रही घटनाओं में नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी कानून-व्यवस्था और सामाजिक परिवेश दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभिभावकों की निगरानी,सोशल मीडिया का प्रभाव, गलत संगत और बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति ऐसे मामलों की बड़ी वजह बन रही है।

पुलिस ने न्यायालय में किया पेश : पुलिस ने पांचों विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि दोनों बालिग आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, नितिन सिन्हा, दीपक दास तथा साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

***बड़ा सवाल :** शहर के बीचों-बीच यदि एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई को सामूहिक रूप से पीटा जाता है,तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सामाजिक सोच और कानून के प्रति भय की स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है। राहत की बात यह है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह घटना इस बात की भी चेतावनी है कि युवाओं और नाबालिगों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा।*

मोदी सरकार के 12 साल पूरे: भाजपा ने लगाई उपलब्धियों की प्रदर्शनी

सेवा,सुशासन और विकास के दावों के बीच रोजगार,महंगाई और जमीनी समस्याओं पर भी चर्चा जरूरी...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा सरगुजा द्वारा '12 साल विश्वास के, विकास के,जनकल्याण के' अभियान के तहत अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। 18 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को चित्रों एवं जानकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज,भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत, युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर तथा जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्र और जानकारियां केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा देश की विकास यात्रा को दर्शाती हैं और यह प्रदर्शनी आम जनता को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने का प्रभावी माध्यम बनेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और जनकल्याण के स्वर्णिम काल के रूप में याद किए जाएंगे। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। यह प्रदर्शनी इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का कार्य करेगी।

जश्न और प्रदर्शनी के बीच कुछ सवाल भी हैं : किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखती है और जनता उसका मूल्यांकन करती है। ऐसे में भाजपा की यह प्रदर्शनी स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधि है,लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उठना लाजिमी है कि क्या केवल उपलब्धियों की तस्वीर दिखाने से विकास का पूरा मूल्यांकन हो सकता है? पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सड़क,रेलवे,हवाई अड्डों,डिजिटल सेवाओं,आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण योजनाओं और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को मजबूत करने के अनेक दावे किए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार महंगाई,बेरोजगारी,किसानों की आय,छोटे व्यापारियों की समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। जनता के बीच चर्चा का विषय यह भी है कि विकास के दावों के साथ इन चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

सरगुजा को क्या मिला,जनता जानना चाहती है : सरगुजा जैसे आदिवासी और पिछड़े अंचल में रहने वाले लोग यह भी जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से क्षेत्र को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिला है...

कितने युवाओं को रोजगार मिला?

- स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हुआ?
- शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया?
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है?
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन से ठोस परिणाम सामने आए?

इन सवालों के जवाब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उपलब्धियों के दावे।

महंगाई और रोजगार का मुद्दा अब भी चर्चा में...

देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रही है,लेकिन आम परिवारों के सामने महंगाई की चुनौती अभी भी बनी हुई है। रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आम लोगों की चिंता का विषय हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में शिक्षित युवा रोजगार के अवसरों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में विकास की चर्चा तभी पूरी मानी जाएगी जब इन मुद्दों पर भी संतोषजनक उत्तर सामने आएं।

प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता : कार्यक्रम में पूर्व सांसद कमल भान सिंह, नगर निगम अध्यक्ष हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला महामंत्री अरुणा सिंह, कार्यक्रम संयोजक विकास पांडेय, मनीष सिंह, मधु चौधरी, निश्चल सिंह, आलोक दुबे, जन्मेजय मिश्रा, मनोज कंसारी, कमलेश तिवारी, रिंकू वर्मा, सावित्री जायसवाल, किरण मिश्रा, शकुंतला पांडेय, देवकी त्रिपाठी, सुभांगी बिहाड़े, निरंजन राय, दीपक सिंह तोमर, प्रयाग साहू, संजीव वर्मा, अभिषेक सिंह देव, निशांत सिंह सोलू, अजय सोनी, विकास शुक्ला, दीपक यादव, सुनीत मिश्रा, सत्यम सिंह, गीता यादव एवं अभिषेक सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जनता की सोच...: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है। लेकिन लोकतंत्र में केवल उपलब्धियों का उत्सव ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता के उन सवालों का जवाब भी जरूरी होता है जो महंगाई,रोजगार, किसानों की आय,स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। सरकार की उपलब्धियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतना ही जरूरी है यह बताना कि जिन समस्याओं को समाप्त करने का वादा किया गया था, उनमें कितना सुधार हुआ और कितनी चुनौतियां अब भी बाकी हैं।

शिवनंदनपुर में विकास का नया अध्याय शुरू,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने ली शपथ

नगर पंचायत बनने के बाद पहली परिषद का गठन,मुख्यमंत्री ने वार्ड क्रमांक 06 में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की...

-संवाददाता-

सूरजपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में बुधवार को लोकतंत्र और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ,जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, पहली बार नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में आए शिवनंदनपुर में आयोजित इस समारोह ने क्षेत्र के विकास की नई उम्मीदों को बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नगर पंचायत क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का भरोसा दिलाते हुए वार्ड क्रमांक 06 में मंगल भवन निर्माण की घोषणा भी की।

अध्यक्ष सहित सात पार्षदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ-

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवानी जायसवाल ने नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश जायसवाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, इसके साथ ही सात पार्षदों ने भी अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लिया,शपथ लेने वाले पार्षदों में श्री श्यामू साहू, प्रमिला साहू, मंजू खेमचंद गोयल,अंजली राजवाड़े,वर्षा जायसवाल,श्री मनी बग्गा एवं श्री प्रशांत अग्रवाल शामिल रहे,समारोह के दौरान क्षेत्रवासियों और समर्थकों में विशेष उत्साह देखने को मिला,बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री बोले- जनता ने विश्वास किया है,अब जिम्मेदारी भी बढ़ी..

बिजली,पानी,सड़क और स्वच्छता को प्राथमिकता देने का आह्वान के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि नगर पंचायत का गठन किसी क्षेत्र के लिए केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं बल्कि विकास की नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम होता है, उन्होंने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से यहां के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, उन्होंने कहा कि नई परिषद को बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनप्रतिनिधियों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का अधिक उपयोग करने की अपील

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री कॉल सेंटर का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की, उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है,उन्होंने लोगों से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का भी आह्वान किया।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम बोले...लंबे समय की मांग हुई पूरी...

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलना क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग की पूर्ति है, उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में सुनियोजित विकास को गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा, उन्होंने नवनिर्वाचित परिषद को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिवनंदनपुर विकास की नई गाथा लिखेगा।

मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात,वार्ड क्रमांक 06 में बनेगा मंगल भवन- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वार्ड क्रमांक 06 में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की, इस घोषणा का उपस्थित नागरिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया,स्थानीय लोगों का मानना है कि मंगल भवन बनने से सामाजिक,सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध होगा,यह भवन क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

लक्ष्मी राजवाड़े ने जताया विश्वास- महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नगर पंचायत का गठन क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, उन्होंने कहा कि नई परिषद सामूहिक प्रयासों और समन्वय के साथ कार्य करते हुए क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कलेक्टर ने प्रस्तुत किया विकास का रोडमैप- कलेक्टर रेना जमील ने मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों को नगर पंचायत शिवनंदनपुर की प्रशासनिक संरचना,विकास संभावनाओं तथा प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत है।

कई मंत्री,सांसद,विधायक और अधिकारी रहे मौजूद- कार्यक्रम में खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भूलन सिंह मरावी, विधायक प्रबोध मिंज, वन विकास निगम मंडल के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

नई परिषद से बढ़ी उम्मीदें- शिवनंदनपुर में पहली बार गठित नगर पंचायत परिषद के गठन के साथ ही क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, अब लोगों को उम्मीद है कि नई परिषद नगर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार,स्वच्छता व्यवस्था,सड़क निर्माण,पेयजल आपूर्ति और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शिवनंदनपुर को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित करेगी।

बिना आवेदन छह बैंकों से निकला 1.05 करोड़ का लोन,कृषि अधिकारी से 57.55 लाख की ठगी

ओटीपी के जरिए रचा गया पूरा खेल,पांच किस्तें भरने के बाद आरोपियों ने किया भुगतान बंद,वेतन खाता भी सीज

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। घर बनाने के लिए 30 लाख रुपए का लोन लेने की कोशिश एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को करोड़ों की ठगी का शिकार बना गई। आरोपियों ने झांसा देकर उनके दस्तावेज और ओटीपी हासिल किए तथा बिना उनकी जानकारी के छह अलग-अलग बैंकों से 1 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए का ऋण स्वीकृत करा लिया। इसके बाद 57.55 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। शुरुआती पांच किस्तें भरकर भरोसा कायम रखा,लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया। अब बैंक पीड़ित से वसूली कर रहे हैं और उनका वेतन खाता भी सीज हो गया है। धौरपुर थाना क्षेत्र के लुण्ड्रा निवासी एवं कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लालसाय राम बखला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में घर निर्माण के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए के लोन की व्यवस्था करने की बात कुछ परिचितों से की थी। इस दौरान उनकी मुलाकात शिवशंकर दास से कराई गई, जिसने मनचाहा लोन दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि शिवशंकर ने आवश्यक दस्तावेज लेकर अलग-अलग बैंकों में प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद विभिन्न बैंकों से आए ओटीपी उसने फोन पर मंगवाए, जिन्हें अधिकारी ने भरोसे में आकर साझा कर दिया। इसके बाद उनके नाम पर आईसीआईसीआई,एचडीएफसी,एसबीआई,एक्सिस बैंक,चोलामंडलम और ग्रामीण बैंक से कुल 1.05 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण स्वीकृत हो गया। जब खाते में अपेक्षा से अधिक राशि पहुंची तो अधिकारी ने आपत्ति जताई। आरोप है कि शिवशंकर ने कहा कि ऋण की 60 प्रतिशत राशि उसे दे दें, बाकी 40 प्रतिशत अपने पास रखें और सभी बैंक ऋण की किस्तें वह स्वयं जमा करेगा। इसी भरोसे में पीड़ित ने आरटीजीएस के माध्यम से 41.05 लाख रुपए तथा अलग-अलग समय में 16.55 लाख रुपए नकद आरोपियों को दे दिए।

पांच किस्तों के बाद बंद कर दिया भुगतान : शिकायत के अनुसार आरोपियों ने केवल पांच मासिक किस्तों का भुगतान किया। इसके बाद ऋण की किस्तें जमा करना बंद कर दिया। नतीजतन सभी बैंकों से वसूली नोटिस आने लगे और पीड़ित का वेतन खाता भी सीज कर दिया गया। इससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। धौरपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिवशंकर दास,सुरेंद्र सिंह, संतोष दास,अरविंद कुमार और आशा मानिकपुरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 61(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बिजली फिर महंगी : ढाई साल में पांचवीं बढ़ोत्तरी,कांग्रेस का पुतला दहन,महंगाई से जनता पर बोझ बढ़ाने का आरोप...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश में बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली दरों में हालिया बढ़ोत्तरी के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने घड़ी चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित क्रमिक आंदोलन का हिस्सा था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में पांचवीं बार बिजली दरें बढ़ाकर आम जनता, किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पाठक ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में लगातार वृद्धि पूरी तरह जनविरोधी फैसला है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने ढाई वर्षों में अब तक कुल 1.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली दरों में वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना को समाप्त कर दिया,वहीं दूसरी ओर लगातार बिजली दरें बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। पाठक ने कहा कि कीमतें बढ़ाने के बावजूद सरकार प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में भी सफल नहीं हो सकी है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा ने कहा कि महंगाई पहले से ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक जरूरत की वस्तुओं तक के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में बिजली दरों में वृद्धि जनता की परेशानियों को और बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी : प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली दर वृद्धि का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने अगले चरण के कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। 18 जून को पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे। इसी दिन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नमना स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी।

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद : पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल, जगन्नाथ कुशवाहा, हेमंत तिवारी, विनीत विशाल जायसवाल, सीमा सोनी, संध्या रवानी, दुर्गेश गुप्ता, अशफाक अली, जीवन यादव, गुरप्रीत सिद्धू, रजनीश सिंह, सोहन जायसवाल, सतीश बारी, दिनेश शर्मा, अमित तिवारी राजा, गीता प्रजापति, गीता रजक, आशीष जायसवाल, शुभम जायसवाल, अमित सिंह, विकास केशरी, विकास शर्मा, आर.डी.एस. चौहान, शिवप्रसाद अग्रहरि, दिलीप धर, काजू खान, संदीप सिन्हा, मिथुन सिंह, केदार यादव, आशीष शील, तीरथ चौधरी, गंगा प्रसाद, वीरेंद्र सिन्हा, रोशन कन्नौजिया, नुजहत फातमा, शकीला सिद्दीकी, रूबी जैन, सरिता महंत, ममता सिंह, अंजू चंद्रवंशी सिंह, अनुराधा सिंह, सपना सिन्हा, अनिता सिन्हा, अंकित जायसवाल, अमित वर्मा, अशोक अग्रवाल, रत्नेश कुमार, परवेज आलम, धनमीत सिंह छाबड़ा, अनिकेत, साहिल, रोहन, राहुल, आर्यमन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

जनता के बीच उठ रहा बड़ा सवाल

बिजली दरों में लगातार वृद्धि के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों के अनुरूप बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और तकनीकी समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में आम उपभोक्ता यह जानना चाहता है कि यदि बिजली महंगी हो रही है तो सेवा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है।

आमजन करें क्या...

बिजली दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर सियासत तेज हो गई है,लेकिन असली चिंता उन लाखों उपभोक्ताओं की है जिनका मासिक घरेलू बजट पहले से महंगाई के दबाव में है। यदि बिजली महंगी होती है तो जनता बेहतर सेवा,कम कटौती और मजबूत व्यवस्था की अपेक्षा भी रखती है। ऐसे में सरकार को सिर्फ दर वृद्धि नहीं,बल्कि उसके औचित्य और उससे मिलने वाले लाभ पर भी स्पष्ट जवाब देना होगा।

महुआ डोरी बीनने गई वृद्धा को हाथी ने कुचला,मौत

कुल्हाड़ी के जंगल में हुआ हादसा, 15-20 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है दंतैल

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम कुल्हाड़ी में बुधवार सुबह एक दंतैल हाथी के हमले में 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला महुआ डोरी बीनकर घर लौट रही थी, तभी जंगल में उसका सामना हाथी से हो गया। सूचना पर वन विभाग और गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वन विभाग ने तत्काल सहायता राशि प्रदान करते हुए मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुल्हाड़ी निवासी कैलाशो बाई (70) बुधवार सुबह गांव से लगे जंगल में महुआ डोरी बीनने गई थीं। लौटने के दौरान अचानक उनका सामना दंतैल हाथी से हो गया। वृद्धा भाग नहीं सकीं और हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय आसपास अन्य ग्रामीण भी जंगल में मौजूद थे। हाथी को देखकर सभी जान बचाकर भाग निकले। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने गांव पहुंचकर परिजनों और वन विभाग को दी। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कराई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। विभाग ने मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की तथा शीघ्र विशेष मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वन विभाग के अनुसार संबंधित दंतैल हाथी पिछले 15 से 20 दिनों से कुल्हाड़ी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इससे पहले वह सूरजपुर और अखोरा क्षेत्र में सक्रिय था, जहां उसके हमले में दो-दो लोगों की मौत हो चुकी है।

आरक्षक से जमीन के नाम पर 1.95 लाख की धोखाधड़ी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक के साथ जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरक्षक संदीप कुमार कश्यप ने कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2016 में भंवर साय से दो लाख रुपए में जमीन का सौदा हुआ था। अनुबंध के बाद उसने 1.95 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी ने आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। रुपये वापस मांगने पर भी इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

नाम सुधार सूचना

हीराचंद गुप्ता, HEERACHAND GUPTAआ. बालमुकुन्द, उम्र 83 वर्ष निवासी गांव रेवटी, सूरजपुर (छ0ग0) यह कि पते का निवासी है।

मेरे नाम से जारी आधार कार्ड में मेरा नाम हरिचंद HARICHAND नाम दर्ज है। जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरा वास्तविक नाम मेरे समस्त प्रमाण पत्रो में हीराचंद गुप्ता HEERACHAND GUPTA दर्ज है, जो सत्य एवं सही है। दोनो नामो में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूं जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता हूं।

शपथग्रहिता
हीराचंद गुप्ता

नाम सुधार सूचना

बाबूलाल आ. सिबाल, उम्र 45 वर्ष निवासी -बरपारा, गांव रवई, पो. डुमरडीह, तह. लुण्ड्रा जिला सरगुजा (छ0ग0) यह कि उपरोक्त पते का निवासी है।यह कि, मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड में उसका नाम का नाम गुलाबी राम GULABI RAM नाम दर्ज है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जन्म प्रमाण पत्र में नाम गुलाब राम GULAB RAM दर्ज है, जो सत्य एवं सही है। यह कि,दोनो नामो में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूं जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता हूं।

शपथग्रहिता
बाबूलाल

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विरेन्द्र कुमार पिता स्व. रामदील, निवासी ग्राम जगदीशपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम जगदीशपुर स्थित खसरा नंबर 241 / 885 रकबा 0.454 हे. भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेखों बी-1, खसरा में आवेदक का नाम त्रुटिवश दर्ज नही है। जबकि वर्ष 1988-89 में आवेदक के पिता रामदिहल आ. नान राम रजवार का नाम दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-16/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा

न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला-सुरजपुर

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

ग्राम कोट के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका फगुनराम आ0 पूरन केवट जाति केवट निवासी ग्राम कोट लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदक/आवेदिका आपने पिता पूरन का विलम्ब मृत्यू प्रमाण पत्र पंजीयन कराने वावत् अनुलब्धता प्रमाण पत्र मय अन्य सहायक दास्तावेज के साथ न्यायलय में आवेदन पत्र पेश किया गया है। मृत्यू दिनांक 21/08/2024

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वम अथवा किसी विविध प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 29/06/2026 को न्यायालयीन समयवधि में उपस्थित कर दावा/आपत्ति पेश कर सकतें है। उसके पयचात दावा आपत्ति में कोई विचार नही किया जायेगा ।

आज दिनांक 15/06/2026 को न्यायलीन पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया ।

नायब तहसीलदार
देवनगर
सील
जिला-सूरजपुर,छ0ग0

दशकर्म के लिए रखे 13 हजार और मोबाइल चोरी

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजिरमा बंगालीपारा में मजदूर के घर से 13,400 रुपए नकद और मोबाइल फोन चोरी हो गया। पीड़ित रमेश दास कोरवा ने बताया कि उसने नवजात बेटी के दशकर्म के लिए रकम जमा कर पेटी में रखी थी। मछली पकडने जाने के दौरान घर में रखा मोबाइल भी चार्जिंग पर था।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

स्थापना, संचालन और रखरखाव हेतु लाइसेंस के आबंटन हेतु ई–नीलामी

कार्य विवरण: तीन वर्ष की अवधि के लिए चाम्पा (CPH), रायगढ़ (RIG) और अंबिकापुर (ABKP) रेलवे स्टेशनों के पार्सल कार्यालय परिसर में प्रचार कियोस्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव के कार्य के लिए लाइसेंसधारी के खर्चे पर लाइसेंस के कार्य हेतु लाइसेंस आबंटन हेतु ई–नीलामी आमंत्रित की गई है। कैटलॉग पहले ही दिनांक **04.06.2026** को आईआरईपीएस वेबसाइट (**https://ireps.gov.in**) पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार है:

कैटेलॉग	श्रेणी	नीलामी दिनांक एवं समय	लॉट क्रमांक	लॉट विवरण	अनुबंध अवधि
MSS-Proksk-3STN	Misc-Static-Services-Promotional Kiosk	22.06.2026 13:00:00	MSS-BSP-CPH-Pro Kiosk 141-26-1	चाम्पा (CPH) रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय परिसर में प्रचार कियोस्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव के कार्य के लिए लाइसेंसधारी के खर्च पर लाइसेंस	1826 दिन
MSS-Proksk-3STN	Misc-Static-Services-Promotional Kiosk	22.06.2026 13:00:00	MSS-BSP-RIG-Pro Kiosk 139-26-1	रायगढ़ (RIG) रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय परिसर में प्रचार कियोस्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव के कार्य के लिए लाइसेंसधारी के खर्चे पर लाइसेंस	1826 दिन
MSS-Proksk-3STN	Misc-Static-Services-Promotional Kiosk	22.06.2026 13:00:00	MSS-BSP-ABKP-Pro Kiosk 140-26-1	अंबिकापुर (ABKP) रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय परिसर में प्रचार कियोस्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव के कार्य के लिए लाइसेंसधारी के खर्चे पर लाइसेंस	1826 दिन

सीपीआर/10/209
सहायक वाणिज्य प्रबंधक – Chg., द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail
Ro.No. :- 145283

'दैनिक घटती-घटना का बड़ा असर, खबर छपते ही रसीद बुक लेकर सूरजपुर पहुंचे पदाधिकारी'

44,300 रुपये का सवाल: चंदा समाज का, हिसाब किसका?

44,300 रुपये पर घिरा कोरिया साहू समाज

73 वोटर के बाद अब 44,300 रुपये का सवाल, आखिर जवाब देगा कौन?

- अध्यक्ष का चुनाव अटका, अब चंदे का हिसाब भी लटका
- माता कर्मा जयंती के नाम पर चंदा वसूला, फिर समाज के खाते में जमा क्यों नहीं हुआ?
- कार्यक्रम सरकारी था तो चंदा क्यों लिया? चंदा लिया तो जमा क्यों नहीं किया?
- रसीद बुक लौटी, लेकिन 44 हजार का हिसाब अब भी गायब

-रवि सिंह-

कोरिया/सूरजपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिला साहू समाज में पिछले छह महीनों से चल रहा नेतृत्व संकट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां अध्यक्ष कौन बनेगा,यह सवाल पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और उसकी जगह एक नया सवाल समाज के बीच चर्चा का विषय बन गया है–आखिर 44 हजार 300 रुपये गए कहां?

अध्यक्ष चुनाव,73 मतदाताओं की सूची, 25 हजार की आबादी,सदस्यता विवाद,चुनाव स्थगन,प्रदेश नेतृत्व का हस्तक्षेप,नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अब रसीद बुक से काटी गई राशि का हिसाब, कोरिया साहू समाज की राजनीति इन दिनों किसी सामाजिक संगठन से ज्यादा किसी चुनावी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी दिखाई दे रही है, दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों के बाद समाज के भीतर जिस प्रकार की हलचल दिखाई दी, उसने यह संकेत जरूर दे दिया कि सवालों की अनदेखी अब आसान नहीं रह गई है।

73 मतदाता,25 हजार आबादी और अब 44 हजार का हिसाब

कोरिया साहू समाज का चुनाव पहले ही पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है,लगभग 25 हजार आबादी वाले समाज में केवल 73 मतदाताओं की सूची सामने आने के बाद लगातार सवाल उठे, फिर सदस्यता अभियान की मांग हुई, फिर चुनाव स्थगित हुआ,फिर प्रदेश नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा,फिर नए पर्यवेक्षक नियुक्त हुए और अब आर्थिक पारदर्शिता का प्रश्न सामने आ गया, यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही समाज के सामने मतदाता सूची, सदस्यता सूची और अब आय-व्यय सूची तीनों का संकट खड़ा हो गया है।

पर्यवेक्षकों के सामने केवल चुनाव नहीं,विश्वास बचाने की चुनौती

प्रदेश साहू संघ ने नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है,लेकिन अब उनके सामने चुनौती केवल अध्यक्ष चुनने की नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाज का विश्वास कैसे बहाल होगा? यदि सदस्यता विवाद बना रहेगा, यदि चंदे का हिसाब स्पष्ट नहीं होगा और यदि समाज के लोगों को जवाब नहीं मिलेगा,तो नया अध्यक्ष चाहे जो बने, विवाद खत्म होने की संभावना कम ही दिखाई देती है।

खबर छपी और रसीद बुक लेकर सूरजपुर पहुंचे पदाधिकारी

15 जून को प्रकाशित खबर में कोरिया साहू समाज के चुनाव,सदस्यता और नेतृत्व संकट को प्रमुखता से उठाया गया था,खबर के प्रकाशन के बाद अचानक संगठन में गतिविधियां तेज हो गईं, जानकारी सामने आई कि कोरिया जिला साहू समाज के पदाधिकारी रसीद पुस्तकों के साथ सूरजपुर पहुंचे और वहां जिला साहू संघ सूरजपुर के पदाधिकारियों से मुलाकात की, यहीं से चर्चा ने नया मोड़ ले लिया, सूरजपुर जिला साहू संघ के महामंत्री द्वारा व्हाट्सऐप समूह में साझा किए गए संदेश में दावा किया गया कि माता कर्मा जयंती महोत्सव के लिए दी गई रसीद पुस्तकों से कुल 44,300 रुपये की राशि काटी गई थी,लेकिन यह राशि जिला साहू संघ सूरजपुर में जमा नहीं हुई, बस फिर क्या था, समाज के भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था।

चंदा लिया गया था तो गया कहां?

वायरल संदेश के अनुसार बैकुंठपुर क्षेत्र से 11,800, सोनहत क्षेत्र से 7,550, बचरा-पटना क्षेत्र से 24,950 कुल राशि ?44,300 अब सवाल यह है कि यदि समाज के नाम पर चंदा लिया गया था तो उसका अंतिम गंतव्य क्या था? क्या राशि समाज के खाते में जमा हुई? यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? यदि राशि की जरूरत नहीं थी तो दानदाताओं को वापस क्यों नहीं की गई? यदि राशि किसी अन्य मद में खर्च हुई तो उसका लेखा-जोखा कहां है? ये वे सवाल हैं जिनका उत्तर समाज का हर सदस्य जानना चाहता है।

नई दलील ये है की कार्यक्रम सरकारी था,इसलिए पैसा जमा नहीं किया

विवाद के बीच यह चर्चा भी सामने आई कि कोरिया साहू समाज के कुछ पदाधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि माता कर्मा जयंती का कार्यक्रम सरकारी सहयोग से आयोजित हुआ था,इसलिए चंदे की राशि जमा नहीं की गई, यदि यह तर्क सही है तो इससे विवाद कम नहीं बल्कि और गंभीर हो जाता है, क्योंकि तब अगला सवाल खड़ा होता है यदि कार्यक्रम सरकारी राशि से होना था तो समाज के नाम पर चंदा क्यों काटा गया? यदि कार्यक्रम के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी तो रसीद पुस्तकों का वितरण क्यों किया गया? यदि लोगों से सहयोग लिया गया था तो वह सहयोग समाज के खाते में क्यों नहीं पहुंचा? और यदि वह राशि समाज के खाते में नहीं पहुंची तो वह किस खाते में पहुंची?

समाज पूछ रहा है...गलती है,लापरवाही है या नीयत का मामला है?

समाज के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि कोई भी संगठन केवल भवन,पद या चुनाव से नहीं चलता। संगठन विश्वास से चलता है, जब लोग समाज के नाम पर रसीद कटवाते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि उनका पैसा समाज के विकास, कार्यक्रमों और गतिविधियों में लगेगा, लेकिन जब उसी राशि का हिसाब मांगना पड़े तो स्थिति असहज हो जाती है, आज समाज के भीतर तीन तरह की चर्चाएं चल रही हैं, पहली–क्या यह केवल लेखा-जोखा की चूक है? दूसरी–क्या राशि जमा करने में प्रशासनिक लापरवाही हुई? तीसरी–क्या कहीं न कहीं नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? हालांकि बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन सवालों का उठना भी स्वाभाविक है।

अध्यक्ष की कुर्सी या समाज का भरोसा?

समाज के कई वरिष्ठ लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि असली लड़ाई अध्यक्ष पद की नहीं है,असली लड़ाई यह तय करने की है कि समाज पारदर्शी तरीके से चलेगा या नहीं,क्योंकि अध्यक्ष बदलते रहते हैं,लेकिन संगठन की साख एक बार चली जाए तो उसे वापस लाने में वर्षों लग जाते हैं, आज कोरिया साहू समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या 44,300 रुपये का पूरा हिसाब सार्वजनिक होगा? क्या दानदाताओं को बताया जाएगा कि उनकी राशि कहां गई? क्या समाज के खाते, आय-व्यय और रसीद पुस्तकों का ऑडिट होगा? और सबसे महत्वपूर्ण क्या नया नेतृत्व इन सवालों का जवाब देगा या फिर यह मामला भी चुनावी नारों और बैठकों के बीच कहीं दब जाएगा? फिलहाल समाज की निगाहें पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों और प्रदेश नेतृत्व पर टिकी हैं,क्योंकि अब मामला केवल चुनाव का नहीं, बल्कि विश्वास,पारदर्शिता और जवाबदेही का बन चुका है। और समाज के लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर चंदा समाज का था, तो हिसाब भी समाज को कब मिलेगा?

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एवं अर्थीफैक्ट्ज आर्टिजंज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

कौशल विकास,स्वरोजगार एवं उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 17 जून 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अंबिकापुर में 16 जून 2026 को विश्वविद्यालय एवं अर्थीफैक्ट्ज आर्टिजंज प्राइवेट लिमिटेड,भोपाल के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय युवाओं को कौशल विकास,स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले की पहल एवं अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी तथा अर्थीफैक्ट्ज आर्टिजंज प्राइवेट लिमिटेड,भोपाल की डायरेक्टर सुश्री अपर्णा अवस्थी ने एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एमओयू के नोडल अधिकारी डॉ. रोहिताश देशमुख,प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग एवं सह-नोडल अधिकारी डॉ. समन नारायण उपाध्याय,सह-प्राध्यापक,विधि विभाग उपस्थित रहे। एमओयू के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शैक्षणिक परिधि में आने वाले हस्तशिल्पियों, कुम्हारों,विशिष्ट कृषि उत्पादकों एवं स्थानीय उत्पादों के संग्रहण एवं विपणन से जुड़े व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग,डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुतीकरण, ब्रांडिंग एवं उद्यमिता विकास संबंधी व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी।

जशपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई,प्रभारी एसडीओ 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

-संवाददाता-

जशपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर की टीम ने जशपुर जिले में एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत मनोरा के प्रभारी एसडीओ (आरईएस) एवं उप अभियंता संजय कुमार दिवाकर को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम कपरोल (हड़िकोना) निवासी एवं पूर्व उप सरपंच रीतु राम यादव ने एसीबी अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कराए गए गेबियन संरचना निर्माण कार्यों के मूल्यांकन और बिल भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रभारी एसडीओ संजय कुमार दिवाकर द्वारा पहले 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में छह माह तक मूल्यांकन लंबित रखने के बाद 50 हजार रुपये की मांग की गई और रकम मिलने पर इंजीनियर भेजकर मूल्यांकन कराया गया। इसके बाद मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन कर बिल भुगतान कराने के एवज में आरोपी ने पुनः 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता रिश्वत देने के बजाय आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। जांच के दौरान मोलभाव के बाद आरोपी 25 हजार रुपये लेने पर राजी हो गया। बुधवार 17 जून 2026 को एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध ट्रैप कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते समय संजय कुमार दिवाकर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई प्रदेश में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्त मुहिम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।

जिले में खुशी की लहर

खेलो इंडिया सेंटर की बालिका खिलाड़ी का रायपुर आवासीय खेल अकादमी में चयन

-संवाददाता-

सूरजपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिले के लिए गौरव का क्षण तब आया जब खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित खेलो इंडिया सेंटर हराटिकरा की एक प्रतिभावान बालिका खिलाड़ी का चयन आवासीय खेल अकादमी रायपुर के लिए हुआ,इस उपलब्धि से न केवल खेल विभाग बल्कि पूरे जिले में उत्साह का माहौल है।

बालिका खिलाड़ी की इस सफलता पर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने उसे फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं,उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा, कलेक्टर श्रीमती जमील ने कहा कि सूरजपुर की बेटियां खेल के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मेहनत, लगन एवं अनुशासन के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, उन्होंने चयनित खिलाड़ी को निरंतर अभ्यास जारी रखने तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आवासीय खेल अकादमी में चयन किसी भी खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, जहां उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी आरती पांडेय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा खेलो इंडिया सेंटर हराटिकरा के प्रशिक्षक प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे, सभी ने चयनित खिलाड़ी को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की, बालिका खिलाड़ी की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण अंचलों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उचित मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिलने पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं।

CMYK

जिला अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत से उठा बवंडर...

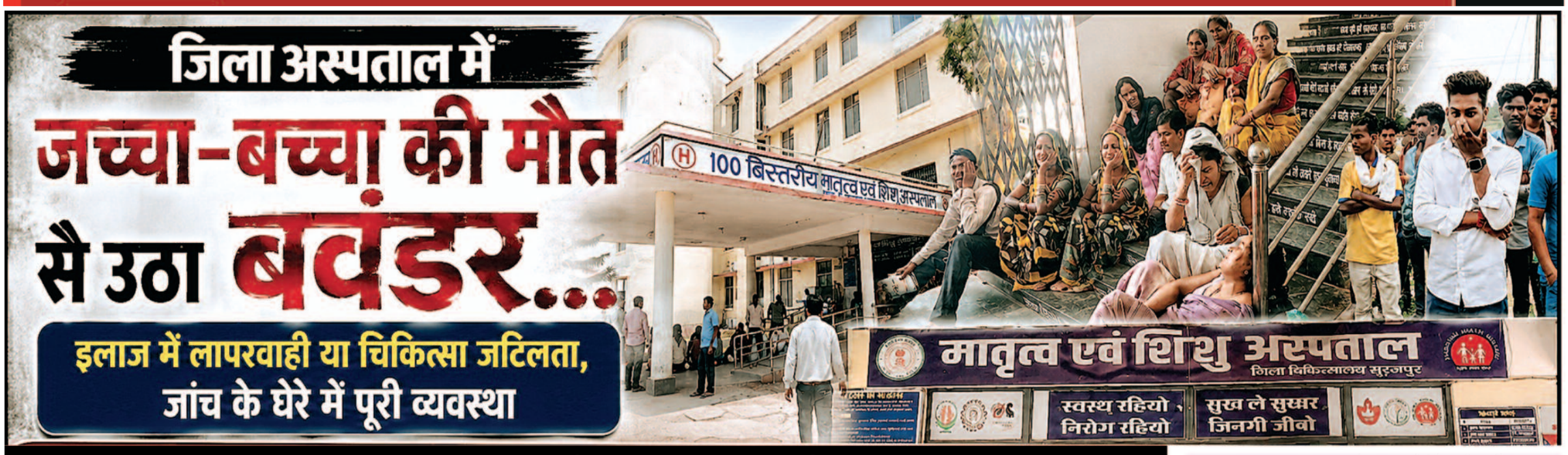

इलाज में लापरवाही या चिकित्सा जटिलता, जांच के घेरे में पूरी व्यवस्था

रामनगर की प्रसूता पूजा मानिकपुरी और नवजात की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा...अस्पताल में हंगामा...स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल सूरजपुर एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है, रामनगर क्षेत्र की निवासी पूजा मानिकपुरी और उसके नवजात शिशु की उपचार के दौरान हुई मौत ने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन लीं,बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं,जिस परिवार में कुछ घंटों बाद नए सदस्य के आगमन की खुशी मनाई जानी थी,वहां अब मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण मां और बच्चे दोनों की जान चली गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन इसे चिकित्सकीय जटिलता का मामला बता रहा है,घटना के बाद जिला अस्पताल परिसर में भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हो गए,मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, परिजनों का कहना है कि यदि समय पर उचित उपचार और गंभीरता से निगरानी की जाती तो मां और बच्चे की जान बचाई जा सकती थी।

प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी पूजा,फिर अचानक बिगड़ गई हालत...

जानकारी के अनुसार रामनगर क्षेत्र निवासी पूजा मानिकपुरी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ ही समय में घर में किलकारियां गूंजेंगी,चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अस्पताल में उनका उपचार शुरू किया गया,परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान पूजा मानिकपुरी को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, परिवार के लोगों का कहना है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला बेचैन होने लगी और कुछ समय के भीतर उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ उपचार में जुटे रहे, लेकिन अंततः महिला की मौत हो गई, इस बीच नवजात शिशु की भी जान नहीं बचाई जा सकी, एक ही परिवार में दो-दो मौतों ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है। अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के अनुसार परिवार के सदस्य लगातार यह सवाल पूछते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि मां और बच्चे दोनों को नहीं बचाया जा सका।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

फिलहाल पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानी जा रही है, यही रिपोर्ट बताएगी कि मौत का वास्तविक कारण क्या था, क्या इंजेक्शन के बाद किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई? क्या महिला पहले से किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी? क्या श्वास नली में उल्टी फंसने की वजह से मौत हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन तब तक जिला अस्पताल में हुई यह दोहरी मौत पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी रहेगी।

सबसे बड़ा सवाल

एक परिवार अस्पताल में नई जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचा था, लेकिन वापस लौटा दो शवों के साथ, अब जांच यह तय करेगी कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चिकित्सकीय जटिलता थी या फिर ऐसी लापरवाही, जिसने एक मां और उसके नवजात की जिंदगी छीन ली, जनता की नजरें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आना उतना ही जरूरी है जितना दोषियों की जवाबदेही तय होना।

परिजनों ने लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई, उनका कहना है कि महिला को समय पर विशेषज्ञ उपचार नहीं मिला और हालत बिगड़ने के बाद भी प्रभावी प्रयास नहीं किए गए, परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, ग्रामीणों का कहना है कि जिला अस्पताल आम लोगों के लिए अंतिम उम्मीद का केंद्र होता है। यदि वहीं मरीज सुरक्षित नहीं हैं तो लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? घटना के बाद ग्रामीणों में भी नाराजगी दिखाई दी और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पारदर्शी जांच की मांग की।

डॉक्टर का पक्ष : महिला पहले से गंभीर थी...

घटना को लेकर ड्यूटी डॉक्टर डॉ. गरिमा सिंह ने अलग पक्ष रखा है, उनके अनुसार महिला की स्थिति पहले से ही सामान्य नहीं थी और उसे देखते हुए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत इंजेक्शन लगाया गया,डॉ. सिंह के मुताबिक इंजेक्शन दिए जाने के बाद महिला को उल्टी हुई और उल्टी का कुछ हिस्सा श्वास नली में फंस गया, इसके कारण उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। चिकित्सकीय टीम ने उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी, डॉक्टरों का कहना है कि कई बार प्रसव के दौरान अचानक उत्पन्न होने वाली चिकित्सकीय जटिलताएं मरीज के लिए घातक साबित हो जाती हैं,हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही संभव होगी।

जांच के आदेश... रिपोर्ट का इंतजार...

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा ने घटना को गंभीर बताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं,उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और विशेषज्ञों की टीम पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करेगी, सीएमएचओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा, रिपोर्ट और जांच निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल...

जिला अस्पताल में हुई यह घटना कई पुराने सवालों को फिर सामने ले आई है, आखिर क्यों अक्सर प्रसूति संबंधी मामलों में विवाद खड़े हो जाते हैं? क्या जिला अस्पतालों में प्रसव संबंधी जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं? क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या पर्याप्त है? क्या गंभीर मरीजों के लिए आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था मजबूत है? ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली अधिकांश गर्भवती महिलाएं जिला अस्पतालों पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में किसी भी प्रसूता की मौत केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं होती, बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा देती है।

शासकीय कर्तव्य अवधि में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय के चिकित्सकों को जारी किए गए निर्देश...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर में पदस्थ चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों द्वारा शासकीय कर्तव्य अवधि के दौरान निजी संस्थानों में प्रैक्टिस किए जाने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि कुछ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक अपनी निर्धारित शासकीय ड्यूटी अवधि के दौरान चिकित्सालय में अनुपस्थित रहकर निजी अस्पतालों एवं क्लीनिकों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है तथा शासकीय दायित्वों एवं मरीजों के प्रति उत्तरदायित्व की अवहेलना को दर्शाता है।

इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी निर्धारित ओपीडी, आईपीडी, ओटी एवं आपातकालीन ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से चिकित्सालय में उपस्थित रहें। औचक निरीक्षण के दौरान यदि कोई चिकित्सक निजी संस्थान में प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है अथवा प्राप्त शिकायतों की जांच में दोषी सिद्ध होता है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शासकीय चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस केवल शासकीय कर्तव्य अवधि के बाहर ही करने की अनुमति है। ड्यूटी अवधि के दौरान स्वयं के क्लीनिक अथवा किसी अन्य निजी अस्पताल, पॉलीक्लीनिक या चिकित्सालय में प्रैक्टिस करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सोशल मीडिया एवं समाचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि निजी अस्पताल एवं संस्थान शासकीय चिकित्सकों अथवा चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं उनकी शासकीय कर्तव्य अवधि के दौरान न लें। यदि कोई निजी संस्था ऐसे चिकित्सकों की सेवाएं लेते हुए पाई जाती है तो संबंधित चिकित्सक के साथ-साथ संस्था के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिजली बिल पर कांग्रेस का हल्लाबोल,CSPDCL कार्यालय का घेराव,मुख्यमंत्री का पुतला दहन

विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस,कहा...महंगाई से त्रस्त जनता पर सरकार डाल रही अतिरिक्त बोझ

-संवाददाता-

सूरजपुर,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश में विद्युत दरों में की गई बढ़ोत्तरी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है,बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली दरों में वृद्धि कर सरकार आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है।

बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन की शुरुआत केतका रोड से हुई, यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए, कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यालय पहुंची, रास्ते भर प्रदर्शनकारी बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करते रहे,रैली में शामिल लोगों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिलों में वृद्धि आम परिवारों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन रही है।

मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विद्युत दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया,कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार को जनता की समस्याओं की चिंता करने के बजाय राजस्व बढ़ाने की चिंता है,पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकता को सरकार आमदनी का माध्यम बना रही है, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है।

महंगाई के बीच बिजली दर बढ़ाना जनता के साथ अन्यायःशशि सिंह

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शशि सिंह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले से ही खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल,गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान है, उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे समय में बिजली दरों में वृद्धि कर सरकार ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, शशि सिंह ने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा को सरकार ने कमाई का साधन बना लिया है, जबकि जनता लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के खिलाफ किसी भी निर्णय का विरोध करती रहेगी और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।

बिजली दरें वापस लेने की मांग,अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में बिजली दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की गई, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जनता को राहत देने के प्रति गंभीर है तो सबसे पहले बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करे।

राजनीतिक संदेश भी,जनहित का मुद्दा भी...

बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आगामी दिनों में प्रदेश की राजनीति में उभरने वाले एक बड़े जनमुद्दे का संकेत भी माना जा रहा है, अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध को किस तरह लेती है और बिजली दरों को लेकर जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं।

यह सिर्फ शुरुआत है,कांग्रेस ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी,चक्का जाम और जिलेव्यापी आंदोलन का ऐलान

जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदर्शन केवल आंदोलन का प्रारंभिक चरण है, यदि सरकार ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पूरे जिले में व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर चक्का जाम,धरना-प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक आंदोलन किए जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है।

कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद,जिला संगठन ने दिखाई एकजुटता

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह के अलावा महामंत्री संजय दोसी, इस्माइल खान, विद्यासागर सिंह, सुनील अग्रवाल, परवेश गोयल, महेंद्र साहू, अरविंद यादव, लवकेश गुर्जर, संतोष पावले, प्रदीप साहू, विक्की समद्दार, अविनाश साहू, चंद्रदत्त दुबे, सुनील सारथी, वेद प्रकाश मिश्रा, रोहन राजवाड़े, अभिकेश सिंह, शक्ति ठाकुर, अजय सोनवानी, लिवनेश सिंह, इमरान अंसारी, दुर्गा टेकाम, सोनू खान, राकेश, छत्रपाल, सुंदर, घूरन प्रजापति, संदीप सिंह, लिली राजवाड़े, जरीना सुल्ताना, प्रेम राजवाड़े, समीर सिंह, आशीष सिंह, सुनील प्रजापति, पारस राजवाड़े, जमील अहमद, राहुल सुनहरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

सीएसपीडीसीएल कार्यालय का घेराव...जमकर हुई नारेबाजी

बिजली विभाग कार्यालय पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरना देते हुए घेराव किया, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और विद्युत दर वृद्धि को वापस लेने की मांग की, प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए माहौल गरमा गया और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों तथा प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक की स्थिति भी बनी, हालांकि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा।

CMYK

खुलेआम गाली-गलौज कर रहे संजय राउत,हद हुई नेतागिरी करने की...

मुंबई,17 जून 2026। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) में बड़ी बगावत की आहट है। 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों के अलग गुट बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत बागी सांसदों पर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने न सिर्फ बागी सांसदों को गालियां दी हैं, बल्कि उन पर 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर मिलने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। संजय राउत ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बागी सांसदों को गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि बेईमानी उनके खून में है। उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी की बात करते हुए राउत ने गालियों का इस्तेमाल किया और कहा, 'ये सा** भो**के लोग।' इतना ही नहीं,राउत ने मीडिया से भी अपील की कि उनकी इन गालियों को सेंसर न किया जाए। राउत ने कहा कि विधायक और सांसद का पद आता-जाता रहता है, लेकिन बाल ठाकरे ने हमें बच्चों की तरह पाला है और उद्धव ठाकरे ने भाइयों की तरह प्यार दिया है,जिसे हम भूल नहीं सकते। उन्होंने पार्टी के तीन नेताओं-अरविंद सावंत,अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे की वफादारी की जमकर तारीफ भी की।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

बिहार की राजधानी पटना की नई टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा

पटना,17 जून 2026। बिहार की राजधानी पटना में जो नई टाउनशिप बनाई जा रही है, उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को किया है। उन्होंने फुलवारीशरीफ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनके पास पटना का नाम बदलने की मांग आ रही थी,लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा निर्णय है,जिसमें एक टाउनशिप को ही पाटलिपुत्र नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इससे शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को महत्व मिलेगा। फुलवारीशरीफ के नदियावां गांव में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जनकल्याण शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि उनकी सरकार बड़े पटना की परिकल्पना पर काम कर रही है, जिसको भविष्य में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक टाउनशिप से राजधानी का स्वरूप बदलेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बता दें कि पटना को प्राचीन समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।

जयपुर में अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले थाने से छूटे,माला पहनाकर हुआ स्वागत

जयपुर,17 जून 2026। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले 5 युवकों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। मंगलवार को विधायकपुरी थाने से रिहाई के बाद लोगों ने आरोपियों का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। वीडियो में समर्थक इंकलाब जिंदाबाद,जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में दिपके जयपुर के शहीद स्मारक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। तभी भीड़ में कुछ समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। इस बीच,कुछ लोग भीड़ में घुस गए और दिपके पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। दिपके के समर्थकों ने हमला करने वाले युवकों को पकड़ लिया और उनकी धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें रोहित शर्मा (उम्र 25 वर्ष), राकेश गुर्जर (उम्र 30 वर्ष),अजय शर्मा (उम्र 25 वर्ष),कुलदीप सिंह शेखावत (उम्र 27 वर्ष), और निकेत (उम्र 28 वर्ष) शामिल हैं।

चुनाव से पहले सपा में होगी बड़ी टूट...योगी सरकार के मंत्री राजभर के बयान से बवाल

दावा-पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने को तैयार

लखनऊ,17 जून 2026। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में किसी नेता का नाम या कोई ठोस साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया। राजभर ने सपा और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने खनन घोटाले और

गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इन मामलों से भलीभांति परिचित

है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

राजनीतिक चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान : सपा का पलटवार

राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल राजनीतिक रूप से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर केवल राजनीतिक चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। साजन ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में राजभर की पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहेगा।

अखिलेश यादव पर पहले भी साध चुके हैं निशाना

यह पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला हो। हाल ही में राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव के विदेश दौरे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि अखिलेश यादव लंदन और पेरिस जाने के बजाय काशी, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य या विंध्याचल जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों का दौरा करते तो स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता। उन्होंने अखिलेश यादव को प्रदेश और देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की सलाह भी दी थी।

एनसीपीआई को मिला नया अध्यक्ष

क्या टीएमसी बागियों की अपील मानेंगे ओम बिरला?

नई दिल्ली,17 जून 2026। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही बगावत के बीच नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में बड़ा बदलाव सामने आया है। पार्टी ने ज्योतिप्रकाश चटर्जी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि काकोली घोष दस्तीदार पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात का खंडन किया है।

काकोली घोष दस्तीदार और बागी सांसदों की भूमिका पर चर्चा : सूत्रों के अनुसार, काकोली घोष दस्तीदार टीएमसी के बागी सांसदों के एक गुट का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर टीएमसी के दो-तिहाई सांसदों के एनसीपीआई में विलय की जानकारी दी थी। अब यह भी चर्चा है कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों–ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और बागी सांसदों–की बात सुनने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले ने संसद में संभावित राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलों को जन्म दिया है।

लोकसभा स्पीकर के फैसले से पहले कानूनी प्रक्रिया पर विचार : इस विवादित मामले में लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय संसद के मानसून सत्र से पहले आने की संभावना जताई जा रही है,जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार, किसी भी

गुट को मान्यता देने से पहले लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय विधि मंत्रालय से लिखित राय भी ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि भविष्य में इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाए, तो स्पीकर का निर्णय कानूनी रूप से मजबूत साबित हो सके। यह प्रक्रिया दलबदल से जुड़े संवैधानिक मामलों में सामान्य रूप से अपनाई जाती है।

सांसदों की संख्या और संभावित राजनीतिक समीकरण : काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि बागी गुट में फिलहाल लगभग 20 सांसद शामिल हैं, और आने वाले समय में यह संख्या 22 तक पहुंच सकती है। एनसीपीआई ने कथित तौर पर टीएमसी के सभी बागी सांसदों को अपने साथ जोड़ने पर सहमति जताई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस गुट का पश्चिम बंगाल विधानसभा में चल रहे बागी विधायकों के विवाद से कोई संबंध नहीं है। विधानसभा स्तर पर अलग गुट को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। यदि लोकसभा में यह बदलाव होता है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

एनडीए गठबंधन में संभावित बदलाव की चर्चा : राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि यह बागी गुट एनसीपीआई के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तो इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत में बदलाव संभव है। इससे एनसीपीआई, टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के बीच सीटों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। माना जा रहा है कि एनसीपीआई 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडीयू से आगे निकल सकती है, जिससे गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बदल जाएगा।

पार्टी नेतृत्व पर सवाल,संगठन में मतभेद उजागर : पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। एनसीपीआई के संगठन महासचिव शांतनु डे ने कहा कि उन्हें ज्योतिप्रकाश चटर्जी की नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है और वे उनके नाम से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर हो रहे बदलावों से संगठन को अंधेरे में रखा जा रहा है,जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। एनसीपीआई, जो 2023 में बनी थी और जिसका मुख्यालय हावड़ा में है, ने त्रिपुरा चुनावों में भी हिस्सा लिया था। अब पार्टी के भीतर नेतृत्व और दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री

उदयन गुहा..कोलकाता से गिरफ्तार,घर दिलाने के नाम पर वसूली की शिकायत

नई दिल्ली,17 जून 2026। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री उदयन गुहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनहाटा के पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक को दिनहाटा थाने की पुलिस ने कोलकाता के फूलबागान इलाके में बने उनके घर से हिरासत में लिया है। उन पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उदयन गुहा पर हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए पक्का मकान योजना के तहत लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि दिनहाटा के बायिंदादा इलाके के लोगों को सरकारी मकान दिलाने के नाम पर वहां की नगरपालिका ने तय नियमों से अलग जाकर 20,000 रुपये अतिरिक्त वसूले थे। जब यह पूरी गड़बड़ी हुई, उस समय उदयन गुहा ही नगरपालिका के चेयरमैन यानी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बैठे थे। इसी वित्तीय हेरफेर के मामले को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूर्व मंत्री की मुश्किलें सिर्फ

इस एक घोटाले तक ही सीमित नहीं हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उनके खिलाफ चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा, विरोधियों को डराने-धमकाने और भ्रष्टाचार से जुड़े कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। इन सभी मामलों को लेकर पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी। दिनहाटा थाने के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह पुलिस की एक स्पेशल टीम दिनहाटा से कोलकाता पहुंची थी। टीम ने पूरी तैयारी के साथ फूलबागान इलाके में छापेमारी की और पूर्व मंत्री को दबोच लिया। बुधवार को पुलिस उन्हें लेकर वापस दिनहाटा थाने पहुंच गई है। गौरतलब है कि बीते 4 मई को दिनहाटा विधानसभा सीट पर आए चुनावी नतीजों में उदयन गुहा भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे।

अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुसीबतें,550 करोड़ के घोटाले में डायमंड हार्बर में दो नई एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली,17 जून 2026। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच अब उनके खुद के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में दो नई एफआईआर दर्ज हो गई हैं। यह मामला कुल 550 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा हैं। भाजपा नेता अभिजीत दास ने यह शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

राहत सामग्री और मिट्टी चोरी का लगा बड़ा आरोप : पहली एफआईआर दक्षिण 24 परगना के कालीतला थाने में हुई है। इसमें करीब 300 करोड़ रुपये की सरकारी मिट्टी चोरी करने का बेहद संगीन आरोप है। वहीं दूसरी एफआईआर विष्णुपुर थाने में दर्ज कराई गई है। यह मामला चक्रवात एंफन के समय का है, जब लोगों

की मदद के लिए आई राहत सामग्री में 250 करोड़ रुपये के हेरफेर की बात कही गई है। खास बात यह है कि इस शिकायत में सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं,बल्कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी सुमित राय और उस समय के कई स्थानीय सरकारी अफसरों के नाम भी शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी इस समय पूरी तरह से केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। पिछले चार दिनों का रिकॉर्ड देखें तो उनसे अलग-अलग मामलों में कुल साढ़े 31 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की टीम उनसे सोमवार को 11 घंटे तक सवाल-जवाब कर चुकी है। इसके अलावा, विधानसभा चुनाव में दिए गए एक भाषण के मामले में सीआईडी ने भवानी भवन में मंगलवार को साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की। वहीं, विधायकों के फर्जी दस्तखत के एक पुराने मामले में भी सीआईडी उनसे दो अलग-अलग दिनों में 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है।

छत्तीसगढ़ समाचार

छत्तीसगढ़ में ईडी का प्रहार! डीएमएफ घोटाले में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद

रायपुर,17 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने अपनी जांच का दायरा और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय की विभिन्न टीमों ने राज्य के पांच प्रमुख जिलों में एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी के इस बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की गई है। यह पूरी कार्रवाई लगभग 575 करोड़ रुपए के कथित डीएमएफ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की जा रही है। जांच की जद में आए इन पांच जिलों में रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर शामिल हैं, जहां कुल नौ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दबिश दी। प्रवर्तन निदेशालय

की टीमों ने नौ अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें चार रिहायशी घर और पांच व्यापारिक परिसर शामिल थे। सबसे अधिक नगद राशि कोरबा और धमतरी के ठिकानों से मिलने की सूचना है। जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख नामों में कारोबारी प्रकाश सालुंके, किशोर एग्रो से जुड़े शाश्वत लुणावत, मानसून एग्रो के प्रमोटर और कांग्रेस के पूर्व सरगुजा जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, तथा ठेकेदार दीपेश गांधी समेत कई अन्य सप्लायर और कारोबारी शामिल हैं। गौरतलब है कि राकेश गुप्ता कृषि विभाग के एक बड़े सप्लायर माने जाते हैं और पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में उनकी फर्म द्वारा की गई सप्लाई पर भी जांच एजेंसियां लगातार अपनी नजरें जमाए हुए हैं। छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक लेनदेन की विस्तृत फाइलें और डिजिटल साक्ष्य हाथ लगे हैं। जांच एजेंसी अब इन बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक लैब में गहन जांच करवा रही है। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य कथित घोटाले में शामिल पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, इस अवैध कमाई के लाभार्थियों और सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले बिचौलियों का पता लगाना है। पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और ठिकानों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि DMF फंड में भारी गड़बड़ी की गई है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित अरबों रुपए की राशि को कथित तौर पर ठेकेदारों, सप्लायरों और बिचौलियों के माध्यम से दूसरे खातों में डायवर्ट किया गया। जांच में सरकारी ठेकों की मंजूरी और परियोजनाओं के काम दिलाने के बदले 25 से 40 प्रतिशत तक कमीशन लिए जाने के गंभीर आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।

भूपेश बघेल को झटका : हाईकोर्ट का चुनाव याचिका रद्द करने से इनकार,अब मेरिट पर होगी सुनवाई

बिलासपुर,17 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है। सांसद विजय बघेल द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी। दरअसल, दुर्ग सांसद व पाटन में भाजपा प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए चुनाव याचिका लगाई है। साल 2024 में लगाई गई इस याचिका में आरोप लगाया गया

है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने चुनावी नारे लगवाए और वोट मांगकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का सीधा उल्लंघन किया। जिसका वीडियो भी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदु पेश कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया है। याचिका खारिज करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था,कोर्ट ने याचिका चलने के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए आवेदन खारिज कर दिया था।

गौ सेवा आयोग अध्यक्ष की गाड़ी पर हमले की कोशिश नशे में धुत युवकों ने की बदसलूकी, गिरफ्तार...

रायपुर,17 जून 2026। कवर्धा के ट्रांसपोर्ट नगर में बुधवार को बड़ा बवाल हो गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेसर पटेल की गाड़ी के साथ न केवल टक्कर हुई, बल्कि नशे में धुत बाइक सवारों ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। विश्वेसर पटेल कवर्धा मुख्यालय से अपने गांव रोहरा लौट रहे थे। तभी अचानक पीछे से आई एक बाइक उनकी कार से टकरा गई। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। कार रुकते ही बाइक सवार दो युवक बाहर आए और जमकर गाली-गलौज करने लगे। सूत्रों के मुताबिक, ये युवक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सड़क से पत्थर उठा लिए और गाड़ी पर

हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया,वरना मामला और भी बिगड़ सकता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विश्वेसर पटेल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन उनके साथ सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दोनों युवक बुरी तरह नशे में थे। उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया और थाने ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने और विवाद करने के चलते दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रविवि के जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स में गड़बड़ी का आरोप : 50 लाख के फंड पर सवाल,सराफा एसोसिएशन ने राज्यपाल से मांगा दखल...

रायपुर,17 जून 2026। रविशंकर विश्वविद्यालय में चल रहे जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स में अनियमितता का मामला सामने आया है। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आरोप है कि 50 लाख का फंड मिलने के बाद भी इस सत्र में प्रवेश न के बराबर हुआ और राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है। सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के नेतृत्व में व्यापारियों ने राज्यपाल को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि राज्य

सरकार ने कोर्स के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, मगर मौजूदा सत्र में छात्रों का प्रवेश नगण्य रहा। व्यापारियों को फंड के मिसयूज की आशंका है। एसोसिएशन ने बताया कि राज्यपाल के निर्देश पर कुलपति से कई बार संपर्क किया गया। लेकिन कोई स्पष्ट या समयबद्ध जवाब नहीं मिला।

चार बड़ी खामियां गिनाईं...

1. कोर्स पर कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई
2. छात्रों के प्लेसमेंट का कोई रोडमैप नहीं
3. प्रवेश बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए
4. विश्वविद्यालय ने कोई औपचारिक पत्राचार तक नहीं किया

'स्किल इंडिया' फेल होने का डर : हरख मालू ने कहा कि यह कोर्स युवाओं को सराफा व्यवसाय में रोजगार और स्किल इंडिया मिशन को मजबूत करने के लिए था। प्रशासनिक लापरवाही से इसका मकसद फेल हो रहा है।

राज्यपाल से की गई ये 3 मांगें...

1. कोर्स का नियमित और पारदर्शी संचालन हो ।
2. 50 लाख की राशि के उपयोग की जांच हो।
3. विवि कोर्स के पुनरुद्धार के लिए टाइमबाउंड प्लान दें।

CMYK

नौगई से उठी आग की लपटें

क्या छत्तीसगढ़ की रेत नीति ने पैदा कर दिया अपना 'भिंड-मुरैना'?

- तीन मौतें,दो जिंदगी और मौत के बीच संघर्षरत,लेकिन सबसे बड़ा सवाल...आखिर इस खूनी खेल का असली जिम्मेदार कौन?
- रेत के ठेके,राजनीतिक संरक्षण,प्रशासनिक खामोशी और बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई ने क्या तैयार कर दिया हिंसा का नया मॉडल?

नौगई हत्याकांड ने केवल अपराध नहीं...पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है...

कोरिया/सोनहत,17 जून 2026 (घटती-घटना)।

नौगई गांव में हुई भीषण घटना केवल एक हत्याकांड नहीं है,यह छत्तीसगढ़ की उस व्यवस्था का आईना है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन,प्रशासनिक निगरानी, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक हितों का ऐसा घालमेल दिखाई देता है, जिसने आज तीन लोगों की जान ले ली और पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, वीरेंद्र सिंह और शिक्षक नागेंद्र सिंह की मौत ने केवल तीन परिवारों को नहीं उजाड़ा,बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां रेत,खदान और वर्चस्व की लड़ाई कानून से बड़ी होती जा रही है,नौगई की घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह केवल हत्या नहीं बल्कि उस पूरे तंत्र की है जिसने ऐसे हालात पैदा होने दिए। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिस रेत का उपयोग घर बनाने के लिए होता है, वही रेत अब लोगों की चिताएं जलाने का कारण बनने लगी?

जब पंचायतों के हाथ में था रेत प्रबंधन,तब क्यों नहीं होती थीं ऐसी घटनाएं?-ग्रामीण क्षेत्रों में आज सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल यही है, एक समय था जब स्थानीय स्तर पर पंचायतें सीमित मात्रा में रेत निकासी और उसके उपयोग की व्यवस्था देखती थीं,उस समय भी रेत निकलती थी,ट्रैक्टर चलते थे,मकान बनते थे,लेकिन शायद ही कभी रेत को लेकर गैंगवार,हत्या,आगजनी और वर्चस्व की ऐसी लड़ाइयां देखने को मिलती थीं,फिर व्यवस्था बदली, रेत खदानों के बड़े ठेके शुरू हुए,करोड़ों रुपये के निवेश होने लगे, बड़े वाहन,बड़े नेटवर्क,बड़े आर्थिक हित और बड़े राजनीतिक समीकरण इस कारोबार में शामिल होने लगे,इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और नियंत्रण की लड़ाई भी, कोरिया,एमसीबी और सूरजपुर जैसे जिलों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेत को लेकर हुए विवाद इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं रह गई है,बल्कि प्रभाव और प्रभुत्व का प्रश्न बन चुकी है।

क्या छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहा है नया 'भिंड-मुरैना'?

मध्यप्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों का नाम लंबे समय तक खनिज,रेत, बाहुबल और गैंगवार की घटनाओं के कारण चर्चा में रहा,वहां खदानों पर नियंत्रण और अवैध कारोबार को लेकर संघर्ष आम बात बन गए थे,आज नौगई की घटना के बाद वही तुलना लोगों की जुबान पर है,यह तुलना केवल भावनात्मक नहीं है,जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा कारोबार इतना लाभकारी हो जाए कि उसके लिए लोग कानून को चुनौती देने लगें,तब स्थिति खतरनाक दिशा में बढ़ने लगती है, पसौरी, जनकपुर, सूरजपुर और अब नौगई की घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि यदि समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

दिन में एफआईआर,रात में मौत—क्या यह केवल संयोग था?-नौगई हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू यह है कि घटना वाले दिन ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी थी,यदि किसी क्षेत्र में दो प्रभावशाली पक्षों के बीच तनाव हो, शिकायत दर्ज हो चुकी हो और कुछ घंटों बाद वही विवाद जानलेवा संघर्ष में बदल जाए,तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे, क्या पुलिस को विवाद की गंभीरता का अनुमान नहीं था? क्या किसी प्रकार की निगरानी या समझाइश का प्रयास किया गया? क्या संभावित हिंसा की आशंका को हल्के में लिया गया? इन सवालों का उत्तर जांच एजेंसियों को देना होगा।

प्रतिबंधित अवधि में रेत का कारोबार आखिर चल कैसे रहा था?-यह प्रश्न शायद सबसे असहज है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मानसून अवधि में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, एनजीटी के दिशा-निर्देश भी स्पष्ट हैं, इसके बावजूद यदि क्षेत्र में रेत को लेकर इतना बड़ा संघर्ष सामने आता है,तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं रेत के कारोबार की गतिविधियां जारी थीं, यहीं से प्रशासनिक जिम्मेदारी का प्रश्न शुरू होता है,क्या खनिज विभाग को जानकारी नहीं थी? क्या स्थानीय प्रशासन को कोई सूचना नहीं मिली? क्या पुलिस को वाहनों की आवाजाही दिखाई नहीं दे रही थी? यदि जानकारी नहीं थी तो यह गंभीर विफलता है। यदि जानकारी थी और कार्रवाई नहीं हुई तो यह और भी गंभीर प्रश्न है।

रेत माफिया नहीं,समानांतर सत्ता का खतरा-नौगई की घटना का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक विवाद नहीं दिखता, यहां शक्ति प्रदर्शन,प्रभाव,भय और नियंत्रण के तत्व भी दिखाई देते हैं,जब किसी क्षेत्र में यह धारणा बनने लगे कि कानून से अधिक प्रभावशाली स्थानीय नेटवर्क हैं, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है, ऐसी स्थिति में आम नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है,आज कोरिया जिले में लोग यही पूछ रहे हैं कि यदि प्रभावशाली लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

पेट्रोल,आग और मौत...क्या यह पूर्व नियोजित साजिश थी?

घटना के बाद लोगों के बीच सबसे अधिक चर्चा उस कथित पेट्रोल को लेकर है, जिससे वाहन में आग लगाए जाने की बात कही जा रही है, यदि किसी वाहन में आग लगाई गई, तो क्या ज्वलनशील पदार्थ पहले से साथ लाया गया था? क्या भारी वाहन पहले से मौके पर मौजूद थे? क्या रास्ता रोकने की तैयारी पहले से की गई थी? ये वे प्रश्न हैं जो पूरे घटनाक्रम को सामान्य विवाद से अलग बनाते हैं, हालांकि इसका अंतिम निष्कर्ष केवल फोरेंसिक जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और न्यायालयीन प्रक्रिया से ही सामने आएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस मामले की जांच केवल हत्या तक सीमित नहीं रह सकती।

तीन मौतों ने खोल दी सिस्टम की परतें...

भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह,वीरेंद्र सिंह और शिक्षक नागेंद्र सिंह की मौत केवल एक आपराधिक घटना का परिणाम नहीं मानी जा सकती,यह उस तनाव, प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक कमजोरी का परिणाम भी प्रतीत होती है जो लंबे समय से बन रही थी,मयंक सिंह और योगेंद्र सिंह अभी भी गंभीर हालत में हैं। उनके बयान पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन जांच चाहे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक बात स्पष्ट है तीन लोगों की मौत के बाद अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होगी।

अब जवाबदेही भी तय होनी चाहिए...

जनता केवल यह नहीं जानना चाहती कि आरोपी कौन हैं, जनता यह भी जानना चाहती है क्षेत्र में रेत कारोबार की निगरानी कौन कर रहा था? प्रतिबंधित अवधि में क्या कार्रवाई हुई? कितने वाहन जब्त किए गए? कितने निरीक्षण हुए? क्या पूर्व शिकायतों को गंभीरता से लिया गया? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो यह धारणा और मजबूत होगी कि हर बड़ी घटना के बाद केवल गिरफ्तारी होती है,लेकिन व्यवस्था की जवाबदेही तय नहीं होती।

नौगई केवल एक गांव नहीं,एक चेतावनी है...

नौगई की घटना को केवल एक पुलिस केस मानना भूल होगी, यह घटना छत्तीसगढ़ के लिए चेतावनी है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यदि पारदर्शी,जवाबदेह और स्थानीय सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, तो ऐसे संघर्ष बढ़ सकते हैं,आज नौगई में तीन चिताएं जली हैं। कल कोई और गांव सुर्खियों में हो सकता है,इसलिए जरूरत केवल अपराधियों को सजा देने की नहीं,बल्कि उस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने की है जिसने ऐसे हालात पैदा होने दिए,क्योंकि कानून केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने का नाम नहीं है,कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य अपराध होने से पहले उसे रोकना भी है, और नौगई की आग यही सवाल छोड़ गई है क्या यह त्रासदी रोकी जा सकती थी? यदि जवाब 'हाँ' है,तो फिर केवल अपराधी ही नहीं,व्यवस्था भी जनता के कठघरे में खड़ी है।

त्वरित टिप्पणी...क्या छत्तीसगढ़ की रेत में घुल रही है भिंड-मुरैना की बारूद?

कोरिया के नौगई में हुई वीभत्स घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं है,यह उस पूरी खनन व्यवस्था पर सवाल है,जो पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में विकसित हुई है,भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, वीरेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह की मौत ने एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर दिया है कि आखिर रेत खदानों की वर्तमान ठेका व्यवस्था ने प्रदेश को किस दिशा में धकेल दिया है,यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर आज जो संघर्ष,गैंगवार,वर्चस्व की लड़ाई और राजनीतिक संरक्षण के आरोप दिखाई दे रहे हैं, वैसी तस्वीर पहले आमतौर पर देखने को नहीं मिलती थी, कभी मध्यप्रदेश के भिंड और मुरैना का नाम सुनते ही लोगों के मन में रेत माफिया, बंदूक, दबंगई, राजनीतिक संरक्षण और खूनी संघर्ष की तस्वीर उभरती थी,आज दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी वैसी ही चर्चा होने लगी है, यह कहना गलत होगा कि पहले अवैध रेत उत्खनन नहीं होता था,रेत पहले भी निकलती थी, बिकती थी और परिवहन भी होता था,लेकिन पंचायत आधारित व्यवस्था में कारोबार अपेक्षाकृत स्थानीय स्तर तक सीमित था,स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रेत निकाली जाती थी और उसका नियंत्रण भी स्थानीय स्तर पर रहता था। बड़े आर्थिक हित, करोड़ों के ठेके और बाहरी प्रभाव अपेक्षाकृत कम थे, स्थिति तब बदली जब रेत खदानों का संचालन बड़े ठेकों और केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से होने लगा, सरकार को राजस्व बढ़ाने का तर्क दिया गया, व्यवस्थित खनन की बात कही गई और यह दावा किया गया कि इससे अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट दिखाई देने लगी,जब कोई ठेकेदार करोड़ों रुपये खर्च करके खदान का ठेका लेता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी लागत निकालने और लाभ कमाने की होती है, यहीं से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। फिर परिवहन मार्गों पर नियंत्रण, बाजार पर पकड़, दूसरे स्रोतों से आने वाली रेत पर आपत्ति, राजनीतिक संरक्षण और प्रभावशाली लोगों की भागीदारी जैसे तत्व प्रवेश करते हैं, धीरे-धीरे यह केवल खनन का विषय नहीं रह जाता,बल्कि आर्थिक वर्चस्व का युद्ध बन जाता है, कोरिया की घटना इसी बड़े संकट का संकेत देती है,आरोपों और चर्चाओं पर यदि विश्वास किया जाए तो विवाद केवल रेत नहीं था, बल्कि रेत के कारोबार पर नियंत्रण का था,सवाल यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियां उस समय पैदा होती थीं जब पंचायतें स्थानीय स्तर पर रेत प्रबंधन करती थीं? प्रदेश के कई हिस्सों में रेत को लेकर विवाद बढ़े हैं, सूरजपुर की घटनाएं हों, जनकपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष हों या अब कोरिया का नौगई कांड—हर घटना के पीछे कहीं न कहीं रेत कारोबार से जुड़े आर्थिक हित दिखाई देते हैं,यह संयोग नहीं हो सकता कि जिन क्षेत्रों में रेत का कारोबार सबसे अधिक लाभकारी हुआ,वहीं विवाद भी सबसे अधिक सामने आए,इसका अर्थ यह नहीं कि पंचायत व्यवस्था पूरी तरह आदर्श थी या उसमें कोई समस्या नहीं थी,लेकिन यह अवश्य है कि वर्तमान व्यवस्था के दुष्परिणाम अब खुलकर सामने आने लगे हैं,यदि किसी व्यवस्था के लागू होने के बाद लगातार संघर्ष,हिंसा,अवैध वसूली,दबंगई और हत्याएं बढ़ रही हों,तो उस व्यवस्था की समीक्षा होना लोकतांत्रिक शासन का दायित्व बन जाता है,सबसे चिंताजनक बात यह है कि रेत अब केवल निर्माण सामग्री नहीं रह गई है। यह राजनीतिक प्रभाव,आर्थिक ताकत और स्थानीय सत्ता का प्रतीक बनती जा रही है,जहां करोड़ों का खेल होगा,वहां संघर्ष भी होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राज्य की नीतियां अनजाने में ऐसे संघर्षों को बढ़ावा दे रही हैं? कोरिया की घटना के बाद सरकार को केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे रेत प्रबंधन मॉडल की समीक्षा की जाए, यह देखा जाए कि पंचायत आधारित व्यवस्था और वर्तमान ठेका व्यवस्था में क्या अंतर आया, किस व्यवस्था में विवाद अधिक बढ़े, किस व्यवस्था में स्थानीय हित सुरक्षित रहे और किस व्यवस्था में अपराधी तत्वों को अवसर मिला,आज छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश विकास और राजस्व के नाम पर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है,जिस रास्ते ने कभी भिंड और मुरैना जैसे क्षेत्रों को रेत माफियाओं की पहचान दी थी? यदि समय रहते इस पर गंभीर चिंतन नहीं हुआ, तो नौगई जैसी घटनाएं अपवाद नहीं बल्कि चेतावनी साबित होंगी, सरकार को यह तय करना होगा कि रेत केवल राजस्व का स्रोत है या फिर सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था का भी विषय है,क्योंकि जब रेत के कारोबार में इंसानी जानें जाने लगें, तब मामला खदानों से निकलकर शासन की प्राथमिकताओं तक पहुंच जाता है, नौगई की आग में केवल तीन लोग नहीं जले हैं, बल्कि एक बड़ा प्रश्न भी धधक रहा है—क्या छत्तीसगढ़ की रेत में अब भिंड-मुरैना की बारूद मिल चुकी है, या अभी भी हालात संभालने का समय बाकी है?

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)